सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

# परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 128, नई दिल्ली, गुरुवार 17 जुलाई 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

**आज का सुविचार**

अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है।

03 लव जिहाद के खिलाफ केंद्र सरकार बनाएं कठोर कानून - स्वामी चक्रपाणि
06 परीक्षा प्रणाली या 'सामाजिक भ्रमजाल?
08 700 साल पुरानी प्रसिद्ध 16 भुजी दुर्गा की देउली मंदिर बना रणक्षेत्र

# दिल्ली में समय सीमा समाप्त हो चुके वाहनों के नाम पर हो चुकी और हो रही जनता के साथ धोखधड़ी और लूटपाट के मामलों में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वह जल्द ही मामले की जांच के देगे आदेश

पिंकी कुंडू सह संपादक परिवहन विशेष

**क्या परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस या दिल्ली नगर निगम के द्वारा आपके पुराने वाहन कबाड़ में डलवा दिए गए या बेच दिए गए तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है**

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा इसकी जांच के आदेश जारी किए जाने की बात कही गई है।

**आपकी जानकारी हेतु बता दें सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय ने पहले ही अपनी आडिट रिपोर्ट और पूर्ण लेखा जोखा जमा नहीं करवाने पर कार्यवाही करते हुए कई आरवीएसएफ को सरकारी नीलामी बोली लगाने से बैन किया हुआ है पर दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम के आला अधिकारी इस बात को जानते हुए भी उन्हीं आरवीएसएफ को दिल्ली में जनता के वाहनों को सुपुर्द करते आ रहे हैं और यह ही वो आरवीएसएफ है जिन्होंने विभागों के नोटिस के बाद भी प्राप्त वाहनों की स्क्रैप कीमत ना तो वाहन मालिकों को दी और ना ही विभागों में जमा करवाई जिसकी निष्पक्ष जांच होना भी आवश्यक है।**

**आपकी जानकारी हेतु बता दें जिन आरवीएसएफ को परिवहन विभाग क्लीन चिट दे रहा है उनकी और उनको क्लीन चिट देने वाले अधिकारी की भी जांच आवश्यक हैं क्योंकि उनके द्वारा वाहन मालिकों को सीओडी जारी ना कर बेचने की शिकायतें दर्ज हैं पर फिर भी इस बात को छुपाया गया है**

**आपकी जानकारी हेतु बता दें की विभागों द्वारा जब्त कर आरवीएसएफ को सुपुर्द किए गए वाहनों की जांच भी आवश्यक हैं क्योंकि ऐसे सबूत उपलब्ध हैं की वाहन ज्यादा सुपुर्द किए गए हैं और दिखाए कम जा रहे हैं**

आपकी जानकारी हेतु बता दें छूट योजना के तहत, नए गैर-परिवहन पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी वाहनों के लिए रियायत 20% और डीजल वाहनों के लिए 15% है, जबकि परिवहन वाहनों के लिए रियायत पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी के लिए 15% और डीजल के लिए 10% है।

**जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों के मालिकों से कई शिकायतें मिलने के बाद, भाजपा की दिल्ली सरकार ईएलवी को जब्त करने में शामिल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) की जांच शुरू करने जा रही है।**

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वह जल्द ही मामले की जांच के आदेश देंगे। जांच में वाहनों को जब्त करने, स्क्रैप करने और रिलीज करने में आरवीएसएफ द्वारा संभावित चूक, कुप्रबंधन और अनियमितताओं की जांच की जाएगी।

**उन्होंने बताया कि इस अभियान में शामिल विभागों, जैसे परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और एमसीडी को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।**

ई.एल.वी. मालिकों ने परिवहन विभाग से शिकायत की है कि पुराने वाहनों को जब्त करने और स्क्रैप करने के लिए अधिकृत





आर.वी.एस.एफ. ने वाहन मालिकों से टोइंग, हैंडलिंग और लॉजिस्टिक शुल्क के लिए अतिरिक्त पैसा वसूला है। "कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें समय पर स्क्रैप मूल्य नहीं मिला और विभाग से अनुमति मिलने के बावजूद आरवीएसएफ ने उनके वाहन नहीं छोड़े। इसके अलावा, हमने देखा है कि यदि वाहन मालिकों को भुगतान भी किया गया, तो उन्हें टोइंग और पार्किंग शुल्क में कटौती के बाद कम स्क्रैप मूल्य मिला, जो दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।" कई लोगों ने शिकायत की है कि आरवीएसएफ वाहन मालिकों को समय पर जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और "गलत सीओडी तैयार कर रहे हैं और मालिक की सहमति के बिना उसका व्यापार कर रहे हैं।"

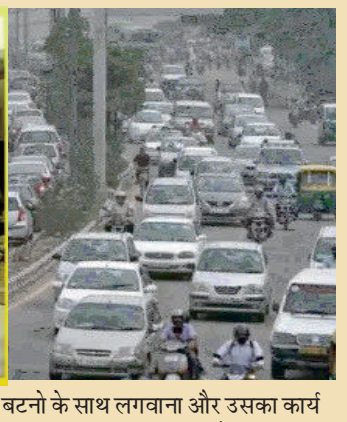

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार "ईएलवी सीओडी और वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र (सीवीएस) उन लोगों को जारी किए जाते हैं जो अपने ईएलवी को आरवीएसएफ से स्क्रैप करवाते हैं। जिस पर मालिक नया वाहन खरीदने पर छूट पाने के लिए सीओडी दिखा सकते हैं। लेकिन स्क्रैपर अवैध रूप से सीओडी बेचकर व्यापार कर रहे हैं" आदेश के अनुसार कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50% से अधिक नहीं हो सकतीं। इसके अलावा, सीओडी जारी होने की तारीख से केवल तीन वर्षों के लिए ही वैध है। इसके अलावा, **नियमों के अनुसार, सरकारी स्वामित्व वाले या ज़ब्त किए गए वाहनों के लिए कोई रियायत उपलब्ध नहीं होगी।** "इसके अलावा, आरवीएसएफ अपने रिकॉर्ड में यह दिखाते हैं कि वाहनों को कबाड़ में बदल दिया गया है, लेकिन वास्तव में वे इन वाहनों को अन्य राज्यों में अवैध रूप से बेचते हैं, कई लोगों ने शिकायत कर बताया है कि उन्हें ऐसे संदेश मिले हैं कि उनके नंबर वाले वाहन विभिन्न राज्यों में टोल टैक्स का भुगतान कर रहे हैं।₹ दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अगर लोग 15 दिनों के भीतर आरवीएसएफ से अपने वाहन वापस नहीं लेते हैं, तो आरवीएसएफ को स्क्रैप की कीमत सरकारी खजाने में जमा करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

परिवहन विभाग ने कुछ महीने पहले इस संबंध में 11 अधिकृत आरवीएसएफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। साथ ही, सभी आरवीएसएफ को स्क्रैप की पूरी कीमत सरकारी खजाने में जमा करने को भी कहा गया था पर उसके बावजूद "स्क्रैपर्स ने अभी तक धनराशि जमा नहीं की है। स्क्रैपर ईएलवी के संचालन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार ऑडिट भी नहीं करते हैं और रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं।"

परिवहन विभाग ने सबसे पहले मार्च 2023 में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया था। हालांकि, कई वाहन मालिकों द्वारा इस अभियान के खिलाफ अदालत का रुख करने के बाद, अदालत ने विभाग को इन वाहनों को हटाने और उनके प्रबंधन के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया था। आपकी जानकारी हेतु बता दें पिछले साल 39,273 वाहन स्क्रैप किए गए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 22,397 था।

# दिल्ली में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों द्वारा बाहरी राज्यों से वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करना दिल्ली की सड़को पर चलने वाली जनता के लिए कितना असुरक्षित

पिंकी कुंडू, सह संपादक परिवहन विशेष

**नई दिल्ली।** पूर्व परिवहन आयुक्त द्वारा एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए आदेश के कारण दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिको को जो परेशानी उत्पन्न हुई थी उसके लिए बार बार आवाज उठाने के बावजूद जब कोई हल नहीं निकाला गया तो वाहन मालिकों द्वारा इस समस्या के हल के लिए अपने वाहनों की जांच फिटनेस प्रमाण पत्र अन्य राज्यों से प्राप्त करना शुरू कर लिया। वाहन मालिकों को अपने वाहनों की जांच प्रमाण पत्र बाहरी राज्यों से समय पर प्राप्त होने से उनकी समस्या का समाधान तो हो गया।

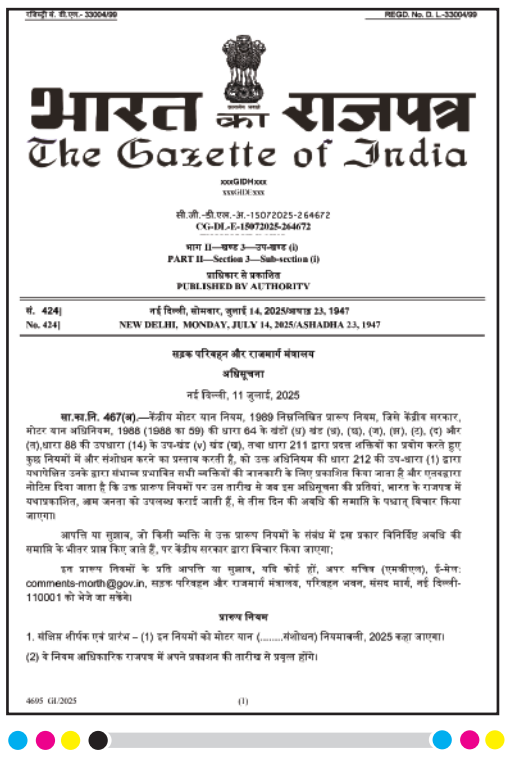

बाहरी राज्यों से प्राप्त वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले वाहनों का दिल्ली की सड़को पर चलना क्या दिल्ली की सड़को पर चलने वाले वाहनों और जनता के लिए हितकारी और सुरक्षित है इस बात पर ना तो उपराज्यपाल दिल्ली, ना दिल्ली सरकार और ना ही परिवहन विभाग के आला अधिकारियों ने कोई सुध ली, आखिर क्यों, बड़ा सवाल?

आपकी जानकारी हेतु बता दें दिल्ली में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया, माननीय उच्च न्यायालय, गृह मंत्रालय सचिव के






नेतृत्व में सम्पन्न कमेटी एवम् दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर कई आदेश पारित है जिनकी जांच वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के समय आवश्यक हैं और जो वाहन बाहरी राज्यों से अपने वाहनों की जांच करवाकर वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करके आ रहे है उनको इन सभी जांचों से मुक्ति मिल जाती हैं और इन सभी जांचों के बिना ही वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता हैं।

ऐसे में सवाल उठता हैं की फिर दिल्ली में अपने व्यवसायिक वाहनों की जांच करवाने वाले वाहनों पर वह पाबंदी क्यो जब बाहरी राज्यों से इन सभी के बिना दिल्ली में ही पंजीकृत व्यवसायिक वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिल्ली की सड़को पर चलने की अनुमति दिल्ली परिवहन विभाग दे रहा है।

आपकी जानकारी हेतु बता दें बाहरी राज्यों से वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले वाहनों के कारण दिल्ली नगर निगम को भी करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा हैं क्योंकि दिल्ली में व्यवसायिक वाहनों की जांच के लिए रूल के अनुसार जमा की जाने वाली फीस के साथ पार्किंग फीस जमा करना अनिवार्य है जो अन्य राज्यों से वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय जमा नहीं होती।

दिल्ली में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों को जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वाहन में वी.एल.टी.डी / जीपीएस संयंत्र पैनिक बटनो के साथ लगवाना और उसका कार्य करता पाया जाना अनिवार्य है जब की बाहरी राज्यों से वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों के लिए अलग अलग स्पीड लिमिट घोषित है और उसकी जांच वाहन जांच प्रमाण पत्र के समय अनिवार्य है पर बाहरी राज्यों से वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले वाहनों को इसकी भी आवश्यकता नहीं होती।

अब आप भी बताए की सिर्फ एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए आदेश के कारण दिल्ली की जनता को सुरक्षा प्राप्त हुई या सड़को पर असुरक्षित जीवन?







# जी.एस.आर. 467(ई) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 से संबंधित अधिसूचना कितनी जन हितकारी, जाने

संजय बाटला

**नई दिल्ली।** जी.एस.आर. 467(ई) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 से संबंधित एक अधिसूचना को संदर्भित करता है। यह विशेष रूप से टोल शुल्क और विभिन्न वाहन-संबंधी सेवाओं पर इसके प्रभाव के मुद्दे को संबोधित करता है। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि टोल शुल्क बकाया है, तो पंजीकरण नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना, बीमा और एनओसी जैसी सेवाएँ रोक दी जाएँगी। यह टोल प्रवर्तन को डिजिटल और प्रक्रियात्मक रूप से सुदृढ़ करने के प्रयास का एक हिस्सा है।

**प्रपत्र और सत्यापन:** अधिसूचना में फॉर्म 28 और अन्य प्रक्रियात्मक नियमों में भी परिवर्तन का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत अब बीमा जारी करने के लिए राष्ट्रीय वाहन रजिस्टर के माध्यम से अवैतनिक बकाया राशि का सत्यापन आवश्यक होगा।

**आपत्तियाँ/सुझाव:** अधिसूचना में 15 जुलाई, 2025 से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां या सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं।

*गुरमीत सिंह तनेजा, अध्यक्ष*
*सीएमवीआर समिति, भारतीय बस एवं कार ऑपरेटर परिसंघ*



रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]



[फा. सं. आरटी-11028/01/2025-एमवीएल]

जी.एस.आर. 467(ई) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 से संबंधित एक अधिसूचना को संदर्भित करता है। यह विशेष रूप से टोल शुल्क और विभिन्न वाहन-संबंधी सेवाओं पर इसके प्रभाव के मुद्दे को संबोधित करता है। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि टोल शुल्क बकाया है, तो पंजीकरण नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना, बीमा और एनओसी जैसी सेवाएँ रोक दी जाएँगी। यह टोल प्रवर्तन को डिजिटल और प्रक्रियात्मक रूप से सुदृढ़ करने के प्रयास का एक हिस्सा है।

# वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर, डीएमई और मेरठ रोड आज रात से नहीं होगा बंद

**गाजियाबाद के वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और मेरठ रोड पर यातायात सामान्य रहेगा क्योंकि कांवड़ियों की संख्या कम है। पहले यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया था लेकिन अब इसे लागू नहीं किया जा रहा है। मेरठ रोड पर कुछ बदलाव किए गए हैं लेकिन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य रहेगा।**

**गाजियाबाद।** वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और मेरठ रोड पर बृहस्पतिवार रात 10 बजे से यातायात नहीं रोका जाएगा। यातायात पुलिस ने पूर्व में डायवर्जन प्लान जारी कर 17 जुलाई की रात से डीएमई और मेरठ रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की थी। लेकिन कांवड़ियों की कम संख्या के कारण दोनों मार्ग पर यह प्लान लागू नहीं किया जा रहा है। मेरठ तिराहे से एनएच-नौ जाने वाले न्यू लिंक रोड को भी बंद नहीं किया जा रहा है। मेरठ रोड पर सोमवार से कादराबाद से मेरठ तिराहे तक वाहनों को गाजियाबाद से मेरठ जाने वाली लेन से आवाजाही कराई जा रही है। मेरठ से आने वाली लेन को पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इससे कई स्थानों पर वाहन चालकों को व्यस्त समय में जाम में फंसना पड़ रहा है। मुरादनगर से गाजियाबाद तक आने में ही डेढ़ घंटा तक लग रहा है। हालांकि दिन में वाहनों का दबाव कम होने पर वाहन चालकों को परेशानी नहीं हो रही। कांवड़ियों की संख्या अभी कम है इसलिए डीएमई और मेरठ रोड पर यातायात नहीं रोका जाएगा।

**नए आदेश तक इन मार्गों पर रहेगी राहत**

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य रहेगा।
मेरठ रोड पर एक ही लेन पर दोनों तरफ का यातायात निकाला जाएगा। मेरठ तिराहे से सीमापुरी बार्डर तक यातायात पूरी तरह से बंद नहीं किया जा रहा।

# एक शानदार हड़ताल के असर में निहित संदेश और सबक

(आलेख : बादल सरोज)

9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में कोई 25 करोड़ हिन्दुस्तानियों की भागीदारी ने उसे सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के लिए भी एक बेमिसाल बड़ी कार्यवाही बना दिया है। दुनिया में कुल अस्तित्वमान 205 देशों में से सिर्फ 5 को छोड़कर किसी भी देश की इतनी आबादी भी नहीं है, जितने लोग 9 जुलाई को भारत में हड़ताल पर गये। महाशक्ति होने का दंभ पाले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी -- इन तीनों देशों की कुल आबादी का जोड़ भी उतना नहीं है, जिससे अधिक लोग 9 जुलाई को हड़ताल पर थे। यह अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी वाली हड़ताल थी, मगर कोई पहली हड़ताल नहीं थी। नीतियों की दुर्गन्ध मारती नालियों और गटरों को मूंदने-पाटने के लिए ऐसी कामयाब हड़तालें और कारगर विरोध कार्यवाहियां तभी से जारी है, जब से इनकी नई और संहारक खेपों की शुरुआत 1991 में आये नवउदारवादी निज़ाम के साथ हुई थी। इसके साथ आयी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के त्रिशूल के खिलाफ इन 34 वर्षों में यह 21 वीं देशव्यापी आम हड़ताल थी। उद्योग और क्षेत्रवार राष्ट्रीय हड़तालों को भी जोड़ लिया जाए, तो यह संख्या सैकड़ों में पहुच जाती है। यह तय है कि संघर्ष आगे भी जारी रहेगा — बल्कि उत्तरोत्तर तीव्र ही होगा, क्योंकि ज़ुल्म, अन्याय और वंचना के खिलाफ लड़ना मनुष्य का स्वभाव है। इन संघर्षों ने ही मनुष्य समाज को बनाया है, उसे जितना भी बन सका, मानवीय और सभ्य बनाया है। इस जद्दोजहद का अभिनंदन है और इसमें शामिल होने वाले, इनके साथ अपनी संबद्धता प्रदर्शित करने वाले धन्य हैं ; उन्होंने अपने इंसान होने का परिचय दिया है। ये पंक्तियाँ इस हड़ताल पर नहीं, इसके असर और उनमें निहित संदेश और सबक पर केन्द्रित हैं।

इस इतनी बड़ी कार्यवाही के प्रति इस देश के कथित मुख्यधारा मीडिया का रुख या तो इसकी पूरी तरह अनदेखी करने का था या इसे पूरी तरह असफल बताने का था। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। पिछले तीन दशक में आमतौर से और गुज़रे एक दशक में ख़ासतौर से मीडिया पर उन कार्पोरेट्स का सम्पूर्ण वर्चस्व कायम हो चुका है, जिनके खिलाफ यह हड़ताल थी। खुद के मारे जाने का तरीका खुद ही बताने वाले भीष्म पितामह सिर्फ पौराणिक कथाओं या महाकाव्यों में ही होते हैं, वास्तविक जीवन में नहीं, पूँजीवाद में तो कतई नहीं। यूं भी वर्गीय समाज में मीडिया हो या तंत्र, शासन हो या प्रशासन, उसका घुटना पेट की तरफ मुड़ने के लिए बना है।

मगर इस बीच बात इससे थोड़ा आगे बढ़ी है और सत्तासमूह के इस अतिआत्मविश्वास में बदल गयी है कि भले कितनी हड़तालें और आन्दोलन हो जाएँ, उसके राज पर कोई आँच नहीं आने वाली। उसे इस बात का यकीन है कि वह अपनी तिकड़मों, झांसों, चालों और भुलावों से इस सारे गुस्से को यदि काफूर न कर सका, तो उसकी दिशा तो बदल ही देगा और इस तरह हुकूमत में बना रहेगा। यह उसकी आज की आजमाई विधा नहीं है — मानव समाज में जब से राज्य अस्तित्व में आया है, तब से ही राज करने वालों ने यह कला अपनाई है और धीरे-धीरे उसमे पारंगतता हासिल कर ली है। ऐसा नहीं है कि इसका ज्ञान सिर्फ उसे ही है। जिन विचारकों और योद्धाओं ने चंद मुट्ठी भर लोगों के समूह के विराट जनता पर राज करने वाली प्रणाली के रहस्य को समझा, इसको बदलने का रास्ता खोजा, सुझाया और व्यवहार में उतारा, वे भी इसे जानते थे। उन्हें पता था कि मानव समाज में सामाजिक रिश्तों, सामाजिक-राजनीतिक जीवन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था आती है और यह अपने आप या अनायास नहीं आती। अवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का रूप पैदावार की ताकतों के विकास के साथ और उसके नतीजे में लेती है। उन्होंने कहा कि इस विकास और बदलाव का आधार उत्पादन की प्रणाली है। यही निर्णायक है। मगर इस निर्णायक यथार्थ को उन्होंने यांत्रिक तरीके से नहीं लिया, उसकी द्वन्द्वात्मकता को भी पकड़ा। उन्होंने कहा कि पैदावार की प्रणाली सिर्फ उत्पादन ही नहीं करती, इसके आधार पर तत्कालीन समाज के दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक विचार भी बनते और आकार लेते हैं, विचारधारा भी आती है और इसी ढांचे पर खड़ी होती है।

कार्ल मार्क्स ने इसे आधार और ऊपरी संरचना — बेस और सुपर स्ट्रक्चर - के रूप में परिभाषित भी किया, इनकी भिन्नता और पारस्परिकता को भी व्याख्यायित किया। उन्होंने जो मार्के की बात कही वह यह थी कि आधार पर खड़ी संरचना सिर्फ उस पर खड़ी नहीं रहती ; वह इसके साथ अंतर्क्रिया भी करती है। मतलब वह इसे प्रभावित भी करती है। इसकी पुष्टि कई तरह से, हर तरह से हुयी है ; दुनिया में अलग-अलग अवस्थाओं की स्थिति में इसने अलग-अलग तरह से भूमिका निबाही है। शोषकों ने अपने से हजारों गुना बड़ी शोषितों की आबादी के लिए इसी संरचना का सहारा लिया है। एक और असाधारण विचारक, फासीवादी दौर के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्तकर ग्राम्शी ने इसे शासक वर्गों द्वारा अपने विचार का प्रभुत्व और वर्चस्व कायम करने और उसका राज चलाने के लिए इस्तेमाल करने के रूप में पहचाना था। खुद मार्क्स ने इसे सपाट तरीके से बयान करते हुए कहा था कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली सिर्फ लोगों के लिए माल ही पैदा नहीं करती, वह अपने माल के लिए लोग भी पैदा करती है। दुनिया भर की शोषक राजसत्ताओं ने यही किया है, भारत में भी यही किया जा रहा है ; अपने माल — हर तरह के माल - के लिए लोग पैदा किये जा रहे हैं। सूचना के क्षेत्र में हुई तकनीकी क्रांति ने उनके इस काम को और आसान बना दिया है।

असली मुद्दों से ध्यान भटकाना, मेहनतकशों की एकता को नष्ट-भ्रष्ट कर देना, गुस्से को इधर-उधर धकेल देना, अतीत के प्रेतों को जगाकर समाज को उन सब बातों के लिए उन्मादी बना देना, जिनका उसकी जिन्दगी और मनुष्यता की बेहतरी से कोई सीधा ताल्लुक ही नहीं है, इसी तरह की आजमाईशें हैं। दुनिया और भारत का जो प्रभु वर्ग है, वह तुलसी के पद "जा को प्रभु दारुण दु:ख देई, ताकी मति पहले हर लेई" पर अक्षरशः अमल कर रहा है। बेहद व्यवस्थित तरीके से आम जन मानस से उसका विवेक छीन रहा है। उसे पाशविकता और अमानुषिकता सिखा ही नहीं रहा, अब तक का सारा सीखा हुआ भुला भी रहा है। मोदी के नए इंडिया में सबसे प्रमुख नया यही है। ऊपर लिखे को दोहराते हुए कहें, तो अपने अनुकूल लोग भी तैयार कर रहा है, अपने लिए सुरक्षित समाज भी बना रहा है।

उसे भरोसा है कि हड़ताल करके गुस्से में नारे लगाती यह भीड़ जलूस और सभाओं के खत्म होने के बाद जैसे ही अलग-अलग मनुष्य के रूप में ठीये लगेगी, अपने घर पहुंचेगी, वह उन्हें दबोच लेगा। उसके घर में लगा टीवी, सुबह आने वाला अखबार, जेब में रखा मोबाइल और कोई कथावाचक उसके बिना जाने ही उसे घसीट कर फिर से उस एजेंडे की कीच में डुबो कर उसका सारा क्रोध, आक्रोश और क्षोभ ठंडा कर देंगे। उसे ऐसे कृत्रिम और काल्पनिक संसार में पहुंचा दिया जाएगा, जहां अम्बानी और अडानी उसे नजर ही आना बंद हो जायेंगे और असली ख़तरा उस असलम और अय्यूब में दिखने लगेगा, जो उसी जैसी या उससे भी बदतर जिन्दगी जी रहे हैं और कुछ घंटा पहले उसी के साथ मुट्ठियाँ ताने नारे लगा रहे थे। उसके हाथ में झंडे की जगह त्रिशूल थमा दिया जाएगा ; आपस में एक-दूसरे में घोंपने के लिए। बात यहीं तक नहीं रुकेगी ; धर्म और मजहब की दीवारों की चौहद्दियों के भीतर भी उसे अपना-पराया ढूँढने तक पहुंचाएगी। शुरुआत 'मेरी जात तेरी जात' से होगी, उसके बाद एक ही जाति में 'मेरे गोत्र तेरे गोत्र' तक जायेगी। अंत में घर की देहरी लांघ कर अन्दर आकर आदमी और औरत के अलगाव और उनमें छोटे-बड़े की खाइयाँ गहरी करते हुए अंततः उसे एकदम तनहा करके ही मानेगी। पता नहीं तब भी मानेगी कि नहीं मानेगी!!

सता पर काबिज गिरोह आश्वस्त है कि ऐसा करते हुए इस गुस्से के असर को वह बेअसर कर देगा और सच्ची बात यह है कि उसकी यह आश्वस्ति निराधार नहीं है। ऐतिहासिक किसान आन्दोलन के बाद हुए चुनावों में इस आन्दोलन के केंद्र रहे दिल्ली के सीमावर्ती प्रदेशों में भाजपा की जीत और बढ़त इसका उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में दसियों लाख की रैलियों और साल दर साल, हर सप्ताह-महीने जनमुद्दों पर हो रहे मैदानी संघर्ष के बाद भी आखिर में ईवीएम की मशीनों पर अँगुलियों का रास्ता भटक जाना इसी की मिसाल है।

सबक यह है कि जिन तरीकों, माध्यमों से हुक्मरान अवाम की ऐसी शानदार कार्यवाहियों के असर से खुद को महफूज रखना चाहते हैं, रखते हैं, उन्हें समझ कर, उनकी काट करके, उन्हें भोंथरा करके ही इन कार्यवाहियों की कारगरता बढ़ाई जा सकती है। यह काम प्रतिरोधात्मक और प्रतिबंधात्मक — मेडिकल साईंस की भाषा में कहें, तो क्यूरेटिव और थेरेपेटिक — दोनों तरह से करना होगा। भ्रांतियों की धूल की धुलाई भी करनी होगी, वे जिस कूड़े में वे पनपती हैं, उसकी सफाई भी करनी होगी। निस्संदेह हड़ताल क्रान्ति के अलावा वर्गीय कार्यवाही का दूसरा सबसे बड़ा रूप है, वर्गीय संघर्ष में मेहनतकश वर्ग की उच्चतर कार्यवाही है। मगर जैसा कि वर्ग संघर्ष को समाज की चालक शक्ति और बदलाव का इंजिन बताने वाले कह गए है ; यह वर्ग संघर्ष सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं होता। विचार, संस्कृति, साहित्य और सामाजिक जीवन शैली सहित हर उस मोर्चे पर होता है, जिनका मनुष्य के जीवन के साथ रिश्ता है।

# विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज

हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, यह दिन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने वाले सबसे गंभीर अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई का सम्मान करने के लिए समर्पित है। यह दिन दुनिया भर में अत्याचारों से निपटने और शांति को बढ़ावा देने में न्याय, जवाबदेही और कानून के शासन के महत्व की याद दिलाता है।

**इतिहास**

============

अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की शुरुआत 17 जुलाई, 1998 को हुई थी, जब रोम संविधि को अपनाया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना की गई थी। ICC पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम है, जब राष्ट्रीय न्यायालय ऐसा करने में असमर्थ या अनिच्छुक हों।

रोम संविधि गंभीर अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन अपराधों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए। रोम संविधि को अपनाने की दसवीं वर्षगांठ पर, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में नामित किया गया था, जिसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस नाम दिया गया।

**महत्व**

========

यह दिवस व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के महत्व को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उन लोगों को जो नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार हैं। यह दण्ड से मुक्ति की समस्या से निपटने तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा में योगदान देने में आईसीसी सहित अंतर्राष्ट्रीय न्याय तंत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह इन अपराधों के पीड़ितों और उत्तरजीवियों के अधिकारों पर भी प्रकाश डालता है तथा उनके लिए न्याय, क्षतिपूर्ति और स्वीकृति की आवश्यकता पर बल देता है।

**कैसे भाग लें**

============

आईसीसी सहित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय तंत्रों तथा वैश्विक शांति एवं न्याय पर उनके प्रभाव के बारे में जानें।

अंतर्राष्ट्रीय न्याय के महत्व और विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की महत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य चैनलों का उपयोग करें।

अंतर्राष्ट्रीय न्याय और मानवाधिकारों पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों या शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लें। अपने समुदाय में न्याय और जवाबदेही की वकालत करें तथा मानवाधिकारों और कानून के शासन को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करें।

# भारत में मतदान का अधिकार केवल देश के नागरिकों को, गैर-भारतीय नागरिक चाहे किसी भी दल से हों, वोट डालने की अनुमति नहीं : राष्ट्रवादी चिंतक राजेश खुराना

**नई दिल्ली,, संजय साग़र सिंह।** बिहार वोटर लिस्ट में विदेशी घुसपैठ के खुलासा पर राष्ट्रवादी चिंतक राजेश खुराना ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में लगभग 7.9 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, लेक्नि प्रारंभिक जांच में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के नाम सामने आए हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या अवैध प्रवासियों की है, तो यह स्थिति अत्यंत गंभीर है। इसके लिए पुरे देश में मतदाता सूची का एक्स-रे जरूरी हैं, यह पुनरीक्षण अभियान भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अवसर है एक ऐसा अवसर जो यह सुनिश्चित करेगा कि वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं को मिले जो इसके वास्तविक अधिकारी हैं। इससे मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित होगी और भविष्य में चुनावों की निष्पक्षता पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं उठ सकेगा और इस सूची को इन्हें वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए जिससे पारदर्शिता और जन भागीदारी को और मजबूत बनाएगा ताकि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में केवल भारतीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉ बाबासाहब के संविधान का अनुच्छेद 326 की भावना यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय लोकतंत्र में केवल पात्र नागरिक ही भाग ले सकें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि निर्वाचन आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी संदेहास्पद नाम की जांच कर सके और आवश्यक होने पर उस नाम को सूची से हटाने का निर्णय ले सके।

**"ना आंसुओं से फर्क पड़ेगा, ना उसकी कहानियों से"**

उन्होंने आगे बताया कि भारत में लोकतंत्र की आधारशिला 'मताधिकार' केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त है और इसमें कोई विरोध या विवाद नहीं होना चाहिए। डॉ बाबा साहब के संबिधान में भारत में मतदान का अधिकार सिर्फ़ भारतीय नागरिकों को हैं, गैर-भारतीय नागरिक चाहे किसी भी दल का सपोटर हों, उसे वोट डालने की अनुमति नहीं हैं। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल या पार्टी से जुड़ा हो, यदि वह भारत का विधिवत नागरिक नहीं है, तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति शरणार्थी हो, चाहे उसकी कितनी भी दु:ख भरी कहानी क्यों ना हो लेक्नि वो वोट नहीं दे सकता औऱ इस में हमेशा कि तरह कोई रोना धोना औऱ छाती पीटकर कोसना नहीं चलेगा। चाहे उसकी कितनी भी दु:ख भरी कहानी क्यों ना हो -- वो आसुओ का समंदर पार करके आग के दरिया से गुजर के ही क्यों ना भारत आया हो -- अगर वह भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं करता, तो लोकतंत्र की इस सबसे अहम प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। इस संदर्भ में संवेदनाएं जरूर हैं, लेकिन कानून के दायरे में भावनाओं के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता। देश डॉ बाबा साहब के संबिधान से चलेगा किसी की ?मनमानी? से नहीं। देशहित में यह साफ है कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत बनाए रखने के लिए यह एक्सरे बहुत जरूरी है कि केवल वही लोग मतदान करें जो विधिवत रूप से भारतीय नागरिक हों चाहे उनकी राजनीतिक निष्ठा या जीवन की कहानी कुछ भी हो। जो भारत का नागरिक नहीं उसे वोट डालने का अधिकार नहीं फिर चाहे वो किनता भी छाती पिटले इसमें कोई मनमानी, रोना-धोना कोसना अब नहीं चलेगा।

# कटु शब्दों का प्रभाव व बोली की मधुरता

हमारा मन अहंकारप्रिय है, स्वार्थप्रिय है, प्रशंसाप्रिय है और अधिकार प्रिय है। अहंकार के टूटने से जो प्रसंग बनता है, उससे स्वार्थ को चोट पहुंचती है, प्रशंसा की उपेक्षा होती है या अधिकार की अवमानना होती है। तब मन क्षण भर में ही मलिन हो जाता है। मन का मलिन रूप ही शब्दों में कटुता उत्पन्न करता है।

कटु शब्दों का सबसे अधिक असर संबंधों पर होता है। संबंधों से समरसता गायब हो जाती है। आक्रोश, आक्षेप और मनमुटाव आ जाता है। जब ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं तो संबंध शव की भांति निर्जीव बन कर रह जाते हैं। शव का तो फिर भी अग्नि संस्कार कर, उससे मुक्त हुआ जा सकता है लेकिन जिंदा लाश बन गए ऐसे संबंधों का न अग्नि संस्कार किया जा सकता है और न ही उन्हें बनाये रखा जा सकता है।

अधरों से बाहर निकले शब्दों की एक और विशेषता है। ये पल भर में अपना असर दिखा देते हैं। ध्यान रहे, गिरगिट को भी अपना रंग बदलने में कुछ समय लगता है। लेकिन हमारे शब्द अपना असर दिखाने में उतना समय भी नहीं लेते। इसलिए सदा अपनी वाणी पर संयम रखें। वाणी को जितना हो सके निर्मल और पवित्र बनाए रखें। मधुर वाणी बोलना एक महंगा लगाव है, जो हर किसी के बस की बात नहीं।

दुखी मूड में बुरे शब्द बिल्कुल न बोलें क्योंकि दुखी मूड को बदलने के बहुत अवसर मिलेंगे। लेकिन शब्दों को बदलने का कोई अवसर नहीं मिलना। एक बार शब्द मुँह से निकला तो फिर निकल गया। उसे आधे रास्ते से लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए जैसे पानी को फिल्टर करके पिया जाता है, वैसे ही मुख से निकलने वाले शब्दों को भी फिल्टर करें। उन्हें सत्य, हितकारी, प्रिय, समयानुकूल, सामाजिक कसौटियों पर कसने के बाद ही मुंह से निकालें।

अंधविश्वास को हटाकर ही सत्य को समझा जा सकता है, जो चीज भीतर है पहले उसे समझना आवश्यक है

बोले गये शब्द, सत्य हितकारी होने पर भी उसकी प्रस्तुति में शालीनता के स्थान पर यदि दंश है, कटुता है और हमारी भाव-भंगिमा उन शब्दों के विपरीत है, तो हमारे कहे गए सत्य को सुन कर भी अनसुना कर दिया जाएगा। इन सारी कसौटियों पर खरे उतरने के बाद भी यदि बोले गए शब्द समयानुकूल नहीं हैं तो हानिकारक ही बनेंगे।

यदि हमें दूसरों के दोष दिखते हैं तो निःसंदेह हमारे शब्द कटु ही होंगे। हर प्रसंग के दो पहलू होते हैं। हम जिस ओर ध्यान देंगे वही हमें दिखाई देगा। अतः इससे बचने का प्रयास निरंतर करें

आनन्द के अवसर पर किसी दुखद प्रसंग का वर्णन कभी नहीं होना चाहिए। इससे विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है जिससे नकारात्मक वातावरण बनता है। ईश्वर के दो निवास स्थान हैं, पहला निर्मल और कृतज्ञ हृदय और दूसरा विनम्र और मृदु कंठ। स्वभाव अच्छा हो, विचार भी अच्छा हो, लेकिन वाणी खराब हो तो संबंध नहीं टिकते। हमारी वाणी मृत्यु और जीवन की कुंजी है। वाणी से ही हमारे गुण और अवगुण जाने जाते हैं। शब्दों की विशेषता है कि यह अनछुए रह कर भी हृदय को छू लेते हैं।

!!!...Sweet Words Always Make Our Relationship Fruitful With Longevity...!!!

**हम बदलें तो दुनिया बदले**

# योग में मन, बुद्धि और आत्मा को तीन अलग-अलग संकल्पनाएं माना जाता है, लेकिन यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर जीवन को प्रभावित करते हैं।

मन, मानसिक स्तर पर विचारों/भावनाओं/संवेदनाओं का केंद्र है। यह हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को सोचता है, विश्लेषण करता है और प्रतिक्रिया करता है। बुद्धि, बौद्धिक स्तर पर हमारे निर्णय लेने की क्षमता है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है और हमारे जीवन में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्मा, आध्यात्मिक स्तर पर हमारे असली स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमारे जीवन का सबसे गहरा और शाश्वत हिस्सा है, जो हमारे जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहता है। इन तीनों का आपसी संबंध बहुत प्रगाढ़ है। मन और बुद्धि को नियंत्रित करके और आत्मा के साथ जुड़कर, हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं।

# पपीता खाने के 6 फायदे जानकर विश्वास करना मुश्किल होगा...

पपीता एक ऐसा फल है जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा।

अगर आपके घर के सामने कुछ जमीन है तो आप इसका पेड़ भी लगा सकते हैं।

ये एक ऐसा फल है जिसे कच्चा होने पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

इसका छिलका बेहद मुलायम होता है जो आसानी से उतर जाता है।

इसे काटने पर इसके भीतर कई छोटे-छोटे काले रंग के बीज होते हैं।

स्वास्थ्य के लिहाज से ये एक बहुत ही फायदेमंद फल है।

अब जानिये इसके अद्भुत फायदे...

(1). कोलेस्ट्रॉल कम करन में सहायक..

पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है।

अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी असरदार है।

(2). वजन घटाने में...

एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती है।

ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में पपीते को जरूर शामिल करें।

इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं।

(3). रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में..

रोग प्रतिरक्षा क्षमता अच्छी हो तो बीमारियां दूर रहती हैं।

पपीता आपके शरीर के लिए आवश्यक विटामिन सी की मांग को पूरा करता है।

ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ मात्रा में पपीता खाते हैं तो आपके बीमार होने की आशंका कम हो जाएगी।

(4). आंखों की रोशनी बढ़ाने में..

पपीते में.. विटामिन सी तो भरपूर होता ही है साथ ही विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में होता है।

विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भी कारगर है।

(5). पाचन तंत्र को सक्रिय रखने में..

पपीते के सेवन से पाचन तंत्र भी सक्रिय रहता है।

पपीते में कई पाचक एंजाइम्स होते हैं।

साथ ही इसमें कई डाइट्री फाइबर्स भी होते हैं जिसकी वजह से पाचन क्रिया सही रहती है।

(6). पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में..

जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान दर्द की शिकायत होती है उन्हें पपीते का सेवन करना चाहिए।

पपीते के सेवन से एक ओर जहां पीरियड साइकिल नियमित रहता है, वहीं पीड़ा में भी आराम मिलता है।

# "प्रेम कभी व्यक्ति से नहीं होता, व्यक्तित्व से होता है"

समझने के लिए कह सकते हैं -
व्यक्ति अर्थात अलग थलग पडा अहंकार।
व्यक्तित्व अर्थात देह का आकार धारण किये जीवात्मा।
परमात्मा साकार, निराकार दोनों है।
जीवात्मा स्वयं निराकार है मगर देह धारण करके वह देहाकार हो जाता है, साकार हो जाता है।
मूल में अहंकार नहीं है(अहंकार भ्रम है) लेकिन जीवात्मा तो है ही।
कृष्ण उसे अपना अंश बताते हैं।
यह अंश ही पूरी देह में व्याप्त होकर देहाकार हो जाता है।
यही व्यक्तित्व है।
और सदा प्रेम करने योग्य है।
जब अलग थलग पडे अहंकार (भ्रम)से प्रेम किया जाता है तब वहां व्यक्ति है।
व्यक्ति जब आपस में प्रेम करते हैं तब वह राग,मोह, आसक्ति का रुप लेता है।
जो समझा हुआ है,सुलझा हुआ है वह व्यक्ति से प्रेम नहीं करता,वह व्यक्तित्व से प्रेम करता है। जीवात्मा की समग्र उपस्थिति से प्रेम करता है।
चाहे वह एक बच्चा ही क्यों न हो!
अक्सर मा बाप बच्चों के लिए समझते हैं कि वे तो डांटने -फटकारने, सुधारने के लिए ही होते हैं।
बहुत कम मां बाप बच्चों को व्यक्ति की तरह लेने के बजाय व्यक्तित्व की तरह लेते हैं।
तब व्यवहार बदल जाता है।
व्यवहार में समग्रता आ जाती है।
इस चर्चा में व्यक्तित्व को अहंकार की तरह नहीं लेना है,समग्र उपस्थिति की तरह लेना है अन्यथा व्यक्तित्व को अहंकार का प्रतीक माना जाता है।
हमें उपरोक्त संदेश को भिन्न संदर्भ में समझना होगा।
इससे बडा समाधान होता है।
पहले के शिक्षक अक्सर बच्चों को प्रताड़ित करते।
वे बच्चों को व्यक्ति की तरह लेते।
यदि वे उन्हें व्यक्तित्व की तरह लेते तो व्यवहार भिन्न होता।
आज डांट फटकार नहीं है(या बहुत कम है) फिर भी बच्चे तो अलग थलग पडे व्यक्ति की तरह ही हैं, व्यक्तित्व की तरह कहां है?
शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जहां बच्चों के साथ उनकी समग्रता को अनुभव करते हुए उत्तमोत्तम व्यवहार किया जाता हो।
व्यक्ति के साथ उत्तम व्यवहार एक कोशिश है, इसमें एक विशेष मानसिकता कार्य करती है।
हमारे घर आने वाले मेहमान को व्यक्ति की तरह देखकर व्यवहार करेंगे तो अलग बात होगी,
व्यक्तित्व की तरह व्यवहार करेंगे तो अलग बात होगी।
अमीर गरीब का सवाल नहीं है, समझने की बात है।
गरीब के घर गरीब मेहमान का स्वागत व्यक्तित्व की तरह हो तो वातावरण में गरिमा होगी।
इसके विपरीत संभव है एक अमीर आदमी, मेहमान का व्यक्ति की तरह स्वागत करता हो, व्यक्तित्व की तरह नहीं।
अहंकार के कारण इसकी संभावना कम होती है।
बहुत कम अमीर ऐसे होंगे जो व्यक्तित्व की तरह हर आगंतुक का स्वागत करते हों।
द्वारिकाधीश के महल में सुदामा किसी अजूबे से कम न थे-दीनहीन,गरीब,फटेहाल।
लेकिन श्रीकृष्ण ने जिस समग्रता के साथ उनका स्वागत किया,उनकी सेवा की उसे सारा जगत जानता है।
इसके लिए कृष्ण ही जिम्मेदार हैं।
महाभारत में ऐसा उदाहरण भी है जिसमें राजा ने निर्धन पूर्व सहपाठी को तिरस्कृत कर दिया था।
व्यवहार स्वयं की समझ पर निर्भर है कि हम किसी व्यक्ति को किस तरह देखते हैं -
व्यक्ति की तरह या व्यक्तित्व की तरह?
व्यक्ति की तरह देखेंगे तो अलगाव होगा, व्यक्तित्व की तरह देखेंगे तो समर्पण जैसा व्यवहार झलकेगा।
एक प्रश्न आता है क्या यह संभव है कि व्यक्ति स्वयं को व्यक्ति की तरह देखे और आगंतुक को व्यक्तित्व की तरह?
यह संभव है अगर आगंतुक प्रतिष्ठित हो, धनवान हो,पदधारी हो और स्वागतकर्ता साधारण हो।
कुछ संभावनाएं हैं -
व्यक्ति स्वयं व्यक्ति की तरह हो, आगंतुक व्यक्तित्व की तरह।
व्यक्ति स्वयं व्यक्तित्व की तरह हो और आगंतुक व्यक्ति की तरह।
या फिर दोनों व्यक्तित्व हों।
एक समग्र उपस्थिति दूसरी समग्र उपस्थिति का स्वागत करती हो।
मेरे आध्यात्मिक मित्र के यहां कोई भी आता तो वह
"आईये"
कहकर उसका भरपूर स्वागत करता।
वह स्वयं भरपूर था।
भरपूर सबके साथ भरपूर जैसा व्यवहार करेगा ही।
कृष्ण की नजर कहां थी सुदामा के फटे कपड़ो पर,
वहां तो समग्रता थी।
अपने मित्र का दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा था।
सुदामा कहां से कहां पहुंच गये!
सुदामा तो तपस्वी थे बाकी प्रेम किसी में भी रचनात्मक परिवर्तन ला सकता है।
बिना प्रेम, उपकार करते हुए किसीकी सेवा की जाय तो उसमें परिवर्तन नहीं आता।
वहां व्यक्ति मौजूद है।
अगर उसे व्यक्तित्व के रुप में लेकर प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाय,उसकी सेवा की जाय,सहयोग किया जाय तो उसके बड़े सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं।
कठिनाई यही है कि अहंकार अपने को ही व्यक्तित्व की तरह देखता है बाकी सबको व्यक्ति की तरह।
वह किसीको व्यक्तित्व की तरह देखेगा तब भी उसके पीछे संकुचित मानसिकता होगी।
सभी को व्यक्तित्व की तरह देखा जाय,हर एक की समग्र उपस्थिति को अनुभव किया जाय तो ही उत्तम परिणाम संभव है।
हम टुकड़ों में बंटकर भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करने की मानसिकता अपनाते हैं,उसे नीति का विषय बनाते हैं तो व्यापक उदारता,हृदय का खुलापन तथा ईश्वरीय प्रेम का होना असंभव है।
जीवात्मा, परमात्मा नहीं है तो उसका अंश तो है। सभी विशेषताएं,सभी गुण उसमें पहले से विद्यमान हैं।
केवल उन्हें पहचानने और प्रकट करने की बात है।
संक्षेप में बात इतनी ही है कि
हमें व्यक्ति से प्रेम नहीं करना है, व्यक्तित्व से(समग्र उपस्थिति से)प्रेम करना है चाहे वह कोई भी हो।
वाकई में सब कुछ पूर्ण है,
पूर्ण की अभिव्यक्ति जो है।
अहंकार स्वयं सम्मानित होना चाहता है।
समझदार सभी को सम्मानित करता और इसलिए स्वयं भी सम्मानित होता है।

# दिल्ली में डीटीसी की 533 बसों के संचालन बंद होने से राहगीर परेशान, मनमाना किराया वसूल रहे रिक्शा और ऑटो ड्राइवर

दिल्ली में DTC की 533 बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। डिम्ट्स के तहत चलने वाली इन बसों का परमिट समाप्त हो गया है जिससे 40 रूटों पर असर पड़ा है। सीमापुरी राजघाट और नजफगढ़ जैसे इलाकों में यात्रियों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। बसें ना चलने से रिक्शा और टैक्सी वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। यात्री घंटों बस का इंतज़ार कर रहे हैं।

**नई दिल्ली।** दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी/DTC) की बसें राजधानीवासियों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनकी आवाजाही से लाखों दिल्लीवासियों के जीने की राह आसान होती है। ऐसे में बुधवार को शहरवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कारण, डीटीसी की 533 बसों के संचालन को रोकने का आदेश दिया गया है। जाहिर है, इससे मुसाफरि परेशान हो गये हैं। वे उमस भरी गर्मी के बीच सड़क पर खड़े होकर अपने बस की राह देख रहे हैं।

**पैसेंजर्स से लेने लगे मनमाना दाम**

बस बंद होने से रिक्शेवाले व टैक्सी वाले पैसेंजर्स से नाज़ायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। टैक्सी में बैठी महिलाएं बस का इंतज़ार कर रही थीं, उन्हें सीमापुरी जाना था। 30 मिनट से बस नहीं आई। महिलाओं के लिए बस फ्री है लेकिन महिलाएं टैक्सी में किराया देकर जा रही है।

**क्यों बंद हो गई डीटीसी की 533 बसें**

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, डिम्ट्स (दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम) के तहत चलने वाली क्लस्टर सेवा की 533 बसें बुधवार से सड़कों से हटाादी गई हैं। इन बसों का परमिट 15 जुलाई तक ही मान्य था। इनके हटने के बाद डिम्ट्स की 3,200 में से 2,700 बसें बच गई हैं।

**इन रूट्स पर हो रही सबसे ज्यादा दिक्कत**

एक साथ 533 बसों का हटना सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। वहीं, तीनों डिपो को मिलाकर करीब 40 रूटों पर ये बसें चल रही थीं। ये बसें सीमापुरी, राजघाट व नजफगढ़ के कैर डिपो की हैं और ये बसें आइएसबीटी कश्मीरी गेट, द्वारका के विभिन्न इलाके, उत्तम नगर क्षेत्र, मध्य दिल्ली के कई क्षेत्र, कापसहेड़ा, नेहरू प्लेस सहित दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में चलती रही हैं।

**क्या इन 533 बसों को दोबारा मिलेगा अवसर**

सूत्रों के अनुसार, ये बसें 10 साल पूरी कर चुकी हैं। इनकी अवधि दो साल और बढ़ाई जा सकती है। बसों की उम्र अभी कई साल बची है, लेकिन परिवहन विभाग ने इन्हें अब और चलने की मंजूरी नहीं दी है।

हालांकि, इन बसों को विस्तार नहीं देने का एक कारण बस डिपो को इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार किया जाना भी माना जा रहा है। ये वही बसें हैं, जन्हिं पिछले 10 साल से डिम्ट्स के तहत संचालति किया जा रहा था। आप सरकार ने जून 2024 में इनका संचालन रोक दिया था, मगर बस संचालक अदालत चले गए थे और उन्हें 15 जुलाई तक विस्तार दिया गया था।

**क्या कहते हैं यात्री?**

"धर्मपुरा बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। एक घंटे से रूट नम्बर 318 की बस आई नहीं है। मैं नोएडा में नौकरी करता हूं। पहले 10 से 20 मिनट में बस मिल जाती थी।"

*-अकबर, यात्री*

"मुझे पटेल नगर से सीमापुरी जाना है। मैं सीलमपुर बस स्टैंड पर उतर गई। यहाँ रूट नम्बर 214 का इंतज़ार कर रही हूं। 30मिनट से बस नही है।"

*- रोजी, यात्री*

# उफ्तत्सा - राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने संपूर्ण राष्ट्र में पार्किंग की समस्या को लेकर फिर उठाई आवाज

परिवहन विशेष न्यूज

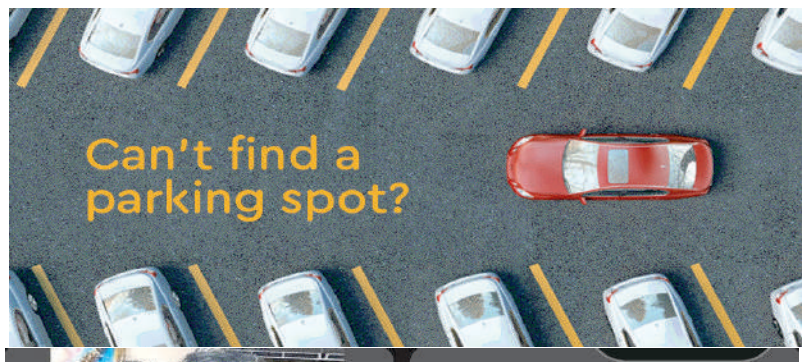


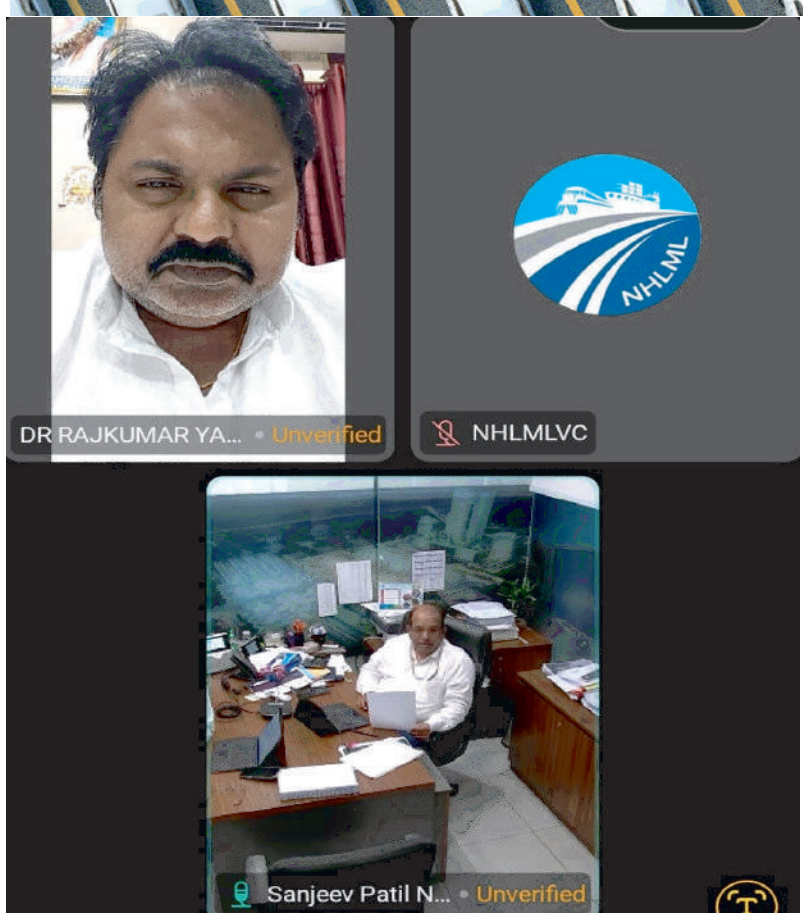


**उफ्तत्सा** – राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने संपूर्ण राष्ट्र में पार्किंग की समस्या को लेकर पहले भी आवाज उठाई व इसी क्रम में दिनांक 15 जुलाई 2025 ऑनलाइन "अपील" के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग व परिवहन मंत्रालय के अधीन - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीनस्थ अधिकारि श्री संजीव पाटिल जी - सी ओ ओ नेशनल हाइवेज़ लोजिस्टिकस मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) से इस विषय में बातचीत की व इसकी गंभीरता से अवगत कराया L विभागीय जानकारी के तहत डॉ यादव को अवगत कराया गया कि संपूर्ण राष्ट्र में 100 से अधिक भारी व्यावसायिक वाहन ट्रक व टेलर के लिए पार्किंग हेतु समुचित व्यवस्था की जा रही है या चालू है आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़कर 160 से ऊपर जाएगी L यहां नहाने, खाने, पार्किंग व अन्य जरूरी व्यवस्था की गयी है L केवल उड़ीसा में ही 10 ऐसे सड़क किनारे व्यवस्था का प्रावधान है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व उड़ीसा राज्य सरकार के बीच एक एम ओ यु भी हुआ है L एक के बाद एक अपनी मांगों को ट्रक मालिक ट्रांसपोर्टर्स व सारथी बंधुओं के हितों की लड़ाई लगातार लड़ने में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ₹उफ्तत्सा ₹ निर्णायक आयाम सफलतापूर्वक गाड़े हैं व भविष्य में भी सतत प्रयास जारी रहेगा L वही डॉक्टर यादव ने विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकायों द्वारा जिला परिषद पंचायत नगर पालिका नगर निगम द्वारा किए जा रहे वसूली के खिलाफ भी जंग छेड़ने की बात की उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहार में ही प्रतिदिन 8 करोड रुपए के लगभग वसूली की जाती है जबकि उड़ीसा में ऐसा नहीं है वहीं कई अन्य राज्य ऐसी वसूलिया कर रहे हैं जिसे भविष्य में पूर्णतया बंद कराया जाएगा व इसके लिए सभी जरूरी करवाई की जायेगी L गाड़ी मालिकों, ट्रांसपोर्टर्स व सारथी बंधुओं के हक़ की अंतिम लड़ाई तक की जिम्मेदारी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा टीम की है व सभी इसे निभाने का भरसक प्रयास करेंगे L

# लव जिहाद के खिलाफ केंद्र सरकार बनाएं कठोर कानून - स्वामी चक्रपाणि

**नई दिल्ली:** अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज अपने ओजस्वी व स्पष्ट विचारों के लिए पहचाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार मनोरंजना गुप्ता के साथ एक पॉडकास्ट में मौजूदा केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने हिंदुओं के हित में बड़े फैसले नहीं लिए। उन्होंने कहा कि लगातार धर्मांतरण की घटनाएं हिंदुओं के साथ होती जा रही है। बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान लगातार भारत में घुसपैठ करते जा रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पर कड़े कदम उठाए। इसके अलावा स्वामी जी ने कहा कि भविष्य में अगर भारत में हिंदू महासभा की सरकार बनेगी तो वह बॉलीवुड पर प्रतिबंध लगाएंगे। उनका मानना है कि बॉलीवुड ने सनातन धर्म की छवि को खराब करने का काम किया है। बॉलीवुड की फिल्मों में सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। केंद्र की मोदी सरकार अपने आप को सनातन धर्म का संरक्षण करने वाली सरकार कहती है मगर इस सरकार की आंख के नीचे फिल्मों के माध्यम से और ओटीटी सीरीज के माध्यम से हमारे देवी देवताओं व साधु संतों का लगातार निरादर किया जा रहा है। इसके अलावा स्वामी जी ने कहा कि सेंसर बोर्ड एक मरी हुई संस्था है इसको बंद किया जाना चाहिए। उदयपुर फाइल्स को लेकर उन्होंने कहा कि इस फिल्म को बड़े पर्दे पर आने से रोका हुआ है। यह फिल्म कन्हैयालाल के ऊपर आधारित है जिनको इस्लामी कट्टरपंथियों ने बहुत बुरी तरह से गला काटकर मार दिया था आज वह सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। मुगल काल के दौरान हमारे अनेक धार्मिक केंद्रों को तोड़ा गया और उन पर मस्जिदों का निर्माण किया गया ऐसे सभी केंद्र जिन पर जबरदस्ती मुगलों ने अपना निर्माण करवाया था वह सारे केंद्र हमें वापस चाहिए। मथुरा, काशी व दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर के निशान मिलते आ रहे हैं। केंद्र सरकार को एक कानून बनाना चाहिए और हमारे सनातन के केंद्र जिन पर इस्लामी शासकों ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है तुरंत वापस हिंदुओं को देना चाहिए। इसके अलावा स्वामी चक्रपाणि महाराज जी ने कहा कि लव जिहाद की घटनाएं हिंदू बालिकाओं के लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए एक खास वर्ग के लोग षड्यंत्र करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार को सत्ता में आए हुए 11 साल हो गए हैं मगर देश में गायों की हत्या लगातार होती जा रही है। भारत विश्व का दूसरे नंबर का देश है जो गौ मास सबसे अधिक मात्रा में निर्यात करता है। गाय हमारी माता है उसकी दुर्गति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार को हिंदुओं के लिए फैसले लेने के लिए और कितना वक्त चाहिए। स्वामी चक्रपाणि जी का कहना है कि भारत को तुरंत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए इसके अलावा गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। लव जिहाद पर तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए। गौशाला मध्य प्रदेश में है जो एक हिंदू मंदिर है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार लंबे समय से है अभी तक गौशाला हिंदुओं को नहीं सोपा गया है। हिंदुओं के मंदिर में मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मनोरंजना गुप्ता से इंटरव्यू के दौरान स्वामी चक्रपाणि महाराज जी ने कहा कि वह चाहते हैं कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किया जाए। पांडवों का यह शहर जिसका नाम अंग्रेजों ने दिल्ली रखा। इस शहर को इसका गौरव दुबारा प्राप्त हो इसलिए इंद्रप्रस्थ नाम होना चाहिए। इसके अलावा स्वामी चक्रपाणि महाराज जी ने कहा कि हिंदू महासभा भविष्य में राजनीतिक लड़ाई लड़कर भी अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी।

# श्रीनिवासपुरी मंडल भाजपा की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर महत्वपूर्ण बैठक

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

**नई दिल्ली।** एक भारत, श्रेष्ठ भारत की दिव्य भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी श्रीनिवासपुरी मंडल में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष हेमबीर भाटी एवं उनकी पूरी टीम द्वारा किया गया।

इस विशेष अवसर पर दक्षिणी दिल्ली की यशस्वी जिलाध्यक्ष माया बिष्ट का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ जो वास्तव में प्रेरणादायक और दिशा देने वाला रहा।

जिला अध्यक्ष माया बिष्ट ने अपने ओजपूर्ण वक्तव्य में यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार हम सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समाज की अंतिम छोर तक पहुँचाकर सेवा, संगठन और समर्पण" के मंत्र को साकार कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता सिर्फ एक सदस्य नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मजबूत स्तंभ है।उनके उद्बोधन ने हम सभी को आत्ममंथन का अवसर दिया और संगठन के प्रति समर्पण को और प्रबल किया। यह बैठक केवल एक आयोजन नहीं थी, यह एक आंदोलन की दिशा में उठाया गया संगठित कदम था। कालकाजी भाजपा नेता धर्मवीर सिंह विधानसभा संयोजक जितेंद्र शर्मा सहसंयोजक मनजीत सिंह जिला उपाध्यक्ष विजय धवन एवं मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।हम सबकी ओर से अध्यक्ष माया बिष्ट का हृदयपूर्वक आभार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा परंपरा को हम सबके सामने एक बार फिर जीवंत कर दिया।

# क्या AI की मदद से दिल्ली के प्रदूषण पर लग जाएगी लगाम? द्वारका में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग किया जाएगा। एआई की मदद से प्रदूषण के कारणों का पता लगाकर नियंत्रण के उपाय किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर द्वारका में ट्रायल शुरू हो गया है जिसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में 190 सेंसर बॉक्स लगाए जाएंगे जो प्रदूषण की निगरानी करेंगे।

**नई दिल्ली।** नासूर बन चुके दिल्ली के वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) की मदद ली जाएगी। एआइ से दिल्ली के अलग- अलग हिस्सों में प्रदूषण के कारकों का पता लगाया जाएगा और फिर उसी के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर द्वारका में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इसके बाद आनंद विहार, पंजाबी बाग व बवाना में ट्रायल किया जाएगा।

केंद्र सरकार के सेंटर फॉर एक्सीलेंस फार एआइ इन सस्टेनेबल सिटीज से मिले आर्थिक सहयोग के आधार पर आईआईटी कानपुर का ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहा है।

जानकारी के अनुसार फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण की निगरानी के लिए 40 एयर क्वालिटी मानिटरिंग स्टेशन लगे हुए हैं। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किमी है। इस हिसाब से एक स्टेशन लगभग 37 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करता है।

फाउंडेशन अब इस दिशा में 190 सेंसर बाक्स लगाएगा। यह बॉक्स दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगेंगे और हर बाक्स के हिस्से में तकरीबन आठ वर्ग किमी का क्षेत्र आएगा। इस तरह ये सेंसर अधिक समीपता से किसी भी क्षेत्र के प्रदूषण की निगरानी कर पाएंगे।

# इसी महीने दिल्ली विधानसभा हो जाएगी पेपरलेस, तेजी से चल रहा है अपग्रेडेशन का काम

दिल्ली विधानसभा का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्य 27 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) शामिल है जिसका उद्देश्य विधानसभा को कागज़ रहित बनाना है। सदस्यों को आईपैड और अन्य आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। आगामी मानसून सत्र से पहले यह कार्य पूरा किया जा रहा है।

**नई दिल्ली:** दिल्ली विधानसभा का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्य मानसून सत्र शुरू होने से पहले 27 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव धर्मेंद्र, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) बिपुल पाठक और अन्य शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।

विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया है कि चल रहे नवीनीकरण कार्य प्रगति पर हैं और अध्यक्ष को अधिकारियों ने अवगत कराया कि 27 जुलाई तक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के साथ यह कार्य पूरा हो जाएगा।

आगामी मानसून सत्र की तैयारी के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है।

अध्यक्ष गुप्ता को विधानसभा के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के कार्यों की जानकारी दी गई, जिसमें राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) परियोजना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य विधानसभा को अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस करके इसे पूरी तरह से कागज रहित सदन में परिवर्तित करना है।

इस आधुनिकीकरण परियोजना के तहत, पारदर्शिता, दक्षता और कागज रहित कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा को नेवा के अंतर्गत एक उन्नत डिजिटल कॉन्फ्रेंस और नेटवर्किंग प्रणाली से सुसज्जित किया जा रहा है।

इस प्रणाली में एकीकृत माइक्रोफोन, वोटिंग पैनल, आरएफआईडी/एनएफसी एक्सेस और बहुभाषी व्याख्या समर्थन वाली स्मार्ट प्रतिनिधि इकाइयां शामिल होंगी। बयान में कहा गया है कि सदस्यों को वास्तविक समय में एजेंडा और दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए आईपैड प्रदान किए जाएंगे।

# पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा- बिहार में चौकाने वाले आंकड़े आए 3.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू

**पूरे भारत की मतदाता सूचियों में संभवत :करोड़ों मतदाताओं के नाम मृत्यु,एक से अधिक सूचियां में नाम दर्ज, जाली प्रमाण व आधार के कारण हटाने से पारदर्शिता बढ़ेगी-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र**

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र पर्व की चर्चाएं पूरी दुनियाँ में होतीरहती है,जो भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाती है, परंतु मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि, इस प्रतिष्ठा में निखार लाने के लिए इसकी त्रुटियां, लीकेजेस, जाली मतदाताओं को पहचान कर सुचियों का पुनरीक्षण,शुद्धिकरण करना समय की मांग है, जिसका क्रियान्वयन बिहार से शुरू हो चुका है जहां 2025 के अंत तक चुनाव होने की चर्चाएं चल रही है वैसे तो, इस तरह के बड़े पुनरीक्षण अभियान पहले भी कई बार हो चुके हैं,1950 के दशक से लेकर 2004 तक कई बार ।लेकिन इस बार काअभियान दो वजहों से अलग है-पहली बार पहले से रजिस्टर्ड वोटर से ही दोबारा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, और दूसरी बार आयोग ने खुद अपनी पुरानी वोटर लिस्ट की वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में देशभर में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और आम लोगों को फिर से खुद को साबित करने के लिए तैयार रहना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि शहरों मेंपलायन बढ़ा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह बस जाते हैं, लेकिन पुराने पते से नाम नहीं हटवाते। इससे एक ही व्यक्ति के नाम दो जगह आ जाते हैं। इसी को ठीक करने के लिए वोटर लिस्ट को साफ किया जा रहा है। राजनीतिक दलों ने भी कई बार फर्जी वोटिंग की शिकायत की है। कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। आयोग का कहना है कि इस तरह की समस्याओं को खत्म करने के लिए ही ये अभियान जरूरी है। बिहार में अब तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 11 तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे थे। इनमें आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और कुछ सरकारी पहचान पत्र शामिल थे। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ आधार,राशन कार्ड और वोटर आईडी ही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर अब आयोग ने तीन दस्तावेज-आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड,को भी शामिल करने पर विचार किया है। ये दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास हैं,खासकरबिहार जैसे राज्यों में ।बिहार में चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाता सूची का 'विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है, जिसे लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है ।लेकिन इसी बीच आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश के बाकी सभी राज्यों को भी ऐसी ही तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि वे 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर मतदाता सूचियों को दोबारा खंगालने की तैयारी शुरू करें। यानी उस दिन तक 18 साल के हो चुके सभी नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हालांकि, इस पूरे अभियान की टाइमलाइन अभी तय नहीं हुई है चूँकि बिहार में 2003 की मतदाता सूचि को प्रमाणिक आधार मानकर संभावित 2.93 करोड़ वर्तमान मतदाताओं पर असर पड़ने की संभावना है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा, बिहार में चौक़ाने वाले आंकड़े आए हैं,35.5 लाख़, मतदाताओं के नाम संभव तो हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संभवतः करोड़ों मतदाताओं के नाम मृत्यु, एक से अधिक सूचियां में नाम दर्ज, जाली प्रमाण व आधार के कारण हटाने से पारदर्शिता बढ़ेगी।

साथियों बात अगर हम बिहार में चल रहे एसआईआर की करें तो 14 जुलाई 2025 को देर रात आई जानकारी के अनुसार, बिहार में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत 35.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के ताजे आंकडों के मुताबिक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अब तक 1.59 प्रतिशत मतदाता मृत पाए गए हैं जबकि 2.2 प्रतिशत मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर जा चुके हैं। इसके साथ ही 0.73 प्रतिशत व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। जिनका कुल योग 4.52 फीसदी है। जो कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में 35.5 लाख हैं ।सोमवार को चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत अबतक 83.66 प्रतिशत मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,60,67,208 मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा किए गए हैं। इस प्रकार, 88.18 पेर्सेंट मतदाताओं ने या तो गणना फॉर्म जमा कर दिया है, या मृत पाए गए हैं, या फिर एक स्थान पर नाम बरकरार रखा गया है अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं।अब केवल 11.82 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा गणना फॉर्म जमा किया जाना शेष है। इनमें से कई ने आने वाले दिनों में दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करने के लिए समय मांगा है। 25 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है। इसके बाद ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा। इसी सूची के आधार पर 2025 के चुनावों की मतदाता सूची तय होगी ।चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए गए प्लेटफॉर्म पर अब तक 5.74 करोड़ से अधिक फॉर्म अपलोड हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म जो पहले की 40 चुनावी ऐप्स को समाहित कर एकीकृत किया गया है।अब ऑनलाइन फॉर्म भरने, नाम खोजने, और दस्तावेज सत्यापन के लिए उपयोग हो रहा है। अब तीसरे चरण में लगभग 1 लाख बीएलओ एक बार फिर घर-घर जाएंगे ।सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलओ) भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। प्रत्येक बूथ लेवल एजेंट प्रतिदिन 50 गणना पत्र तक जमा और प्रमाणित कर सकता है। 261 नगर निकायों के 5,683 वार्डों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र शहरी मतदाता सूची से बाहर न रहे ऐसा पूरा प्रयास हो रहा है।

साथियों बात अगर हम पूरे भारत में एसआईआर लागू करने की करें तो,फिलहाल जो संकेत मिल रहे है, उनमें अगले दो सालों में इसे चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों में लेकर वह जाएगा। जिसकी शुरूआत अगले महीने से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल सहित पांच राज्यों से हो सकती है। इन सभी राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी है। इस पूरे अभियान को लेकर सबसे ज़्यादा डर हाशिए पर जी रहे लोगों में है। ईबीसी, दलित, मुसलमान और गरीब तबके के लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका नाम ही न कट जाए। कुछ इसे "पीछे से लाया गया एनआरसी" कह रहे हैं। मतलब बिना सीधे कहे नागरिकता की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में इस प्रक्रिया को रोकने से तो मना कर दिया, लेकिन चिंता जताई कि कहीं चुनाव से पहले किसी का नाम लिस्ट से हट गया, तो उसका वोट देने का अधिकार ही छिन जाएगा। कोर्ट ने आयोग को सुझाव दिया कि दस्तावेज़ी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा-बिहार में चौकाने वाले आंकड़े आए 3.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरूबिहार में 2003 की मतदाता सूची को प्रमाणिक आधार माना-संभावित 2.93 करोड़ वर्तमान मतदाताओं पर असर पड़ने की संभावना ?पूरे भारत की मतदाता सूचियों में संभवतःकरोड़ों मतदाताओं के नाम मृत्यु, एक से अधिक सूचियां में नाम दर्ज, जाली प्रमाण व आधार के कारण हटाने से पारदर्शिता बढ़ेगी।

## जीत रहा कलयुग , हार रहा सतयुग

एक दूसरे को हराने में बन रहा है दानव।
पहचान छुपा ली खुद की कौन है मानव ।।
काम, क्रोध, मोह, लोभ की ओर जा रहा।
अपने संस्कारों को पश्चिमी संस्कृति में उड़ा रहा ।।
क्योंकि जीत रहा है कलयुग और हार रहा है सतयुग.....

अब न आएंगे राम और न कृष्ण आएंगे।
विस्तृत धर्म का मार्ग न तुम्हे बताएंगे।।
खुद ढूंढने होंगे तुम्हे धर्म के आयाम।
मिले मूल्य धर्म के तो भेजना पयाम।।
क्योंकि जीत रहा है कलयुग और हार रहा है सतयुग.....

जैसे त्रेता में हुआ था रावण का अंत।
जैसे द्वापर में हुआ था कंस का अंत।।
वैसे ही कलयुग को हराने का एक मात्र तप।
अंतर्मन से करना होगा नाम जप।।
क्योंकि जीत रहा है कलयुग और हार रहा है सतयुग.....

**-रजत पडियार**
**04, अपना टेलर्स ,धनजी भाई का नोहरा ,रतलाम**

## राष्ट्र गौरव शुभाशु

देश के सपूत ने रचा नया इतिहास।
भूमंडलीय दौड़ में हमें मिला विश्वास।।
अष्टादश अंतरिक्ष में, गुजरे कठिन वो दिन।
घौर साधना बल से ,आज आया शुभ दिन।।
भाल भारत का ऊंचा हुआ,गर्व से फुला सीना।
मित्र राष्ट्र हर्षित हुए ,दुश्मन पसीना पसीना।।
राष्ट्र गौरव शुभांशु का ,मां भारती को वंदन।
मस्तक पर सुशोभित हुआ मलियागिरी सा चंदन।।
धन्य हुई आशा कामना गर्वित शुक्ला दयाल।
देश जिस पर नाज करें मां ने जाया ऐसा लाल।।
चिरंजीवी हो सिंह शुभांशु ,सबकी यही है शुभकामना।
विश्व गुरु देश बने ,राष्ट्र की यही मनोकामना।।

**रचनाकार**
**दिनेश बारोठे दिनेश´**

## 70 वर्षीय लालता प्रसाद की मंगलवार की रात तालाब में डूबने से मौत

परिवहन विशेष न्यूज

**बिनावर:** थाना बिनावर क्षेत्र के सराय गांव निवासी 70 वर्षीय लालता प्रसाद की मंगलवार की रात तालाब में डूबने से मौत हो गई। लालता प्रसाद रात में लगभग सात - आठ बजे शौच करने तालाब की ओर गया था। शौच के बाद तालाब में पानी छूते वक्त पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया।

वहीं गांव के तालाब में 10 फिट से ऊपर पानी भरा है। बुजुर्ग लालता प्रसाद को पानी में तैरना नहीं आता था, जिसके कारण वह डूब गया। अगले दिन सुबह प्रातः लालता प्रसाद का शव पानी में तैरते हुए गांव के किसी व्यक्ति ने देखा। जिसने गांव में जाकर लोगों को बताया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन और ग्रामीण तालाब के पास पहुंचे। इसके बाद, पानी मे तैरते युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। घटना के बाद स्वजनों के बीच चीख-पुकार मच गया।

## डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी श्री ध्यानमूर्ति सत्संग सेवा संस्थान द्वारा "सेवा सहयोग सम्मान" से अलंकृत

परिवहन विशेष न्यूज

**वृन्दावन।** परिक्रमा मार्ग/गौशाला नगर स्थित श्रीराधा रानी प्रसादम भवन में श्री ध्यानमूर्ति सत्संग सेवा संस्थान के द्वारा नगर के प्रख्यात साहित्यकार, अध्यात्मविद्, समाजसेवी डॉ. गोपाल चतुर्वेदी,एडवोकेट को उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गईं अविस्मरणीय सेवाओं के लिए ₹सेवा सहयोग सम्मान₹ से अलंकृत किया गया।उन्हें ये सम्मान संस्थान की अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी मां ध्यानमूर्ति गिरि महाराज ने प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और ठाकुरजी का पटका-प्रसादी-माला आदि भेंट करके दिया। साथ ही प्रभु से उनके उज्वल, सुखद, समृद्ध और मंगलमय जीवन की कामना की।

महामंडलेश्वर स्वामी मां ध्यानमूर्ति गिरि महाराज ने कहा कि डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी श्रीधाम वृंदावन के गौरव है। उनके द्वारा हमारे संस्थान के विभिन्न सेवा प्रकल्पों में जो अमूल्य सहयोग प्रदान किया जा रहा है, वो अति प्रशंसनीय है ।हमारा संस्थान उनका सम्मान करके स्वयं गौरान्वित हो रहा है।

इस अवसर पर संस्थान के सचिव डॉक्टर हरिओम शास्त्री, प्रमुख समाजसेवी

विष्णु शर्मा और युवा साहित्यकार डॉक्टर राधाकांत शर्मा आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थिति रहे।

## राउरकेला महानगर निगम में लूट के खेल पर एनसीपी (अजित गुट) का वार

**प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने उठाए सवाल, सीएम से लेकर पीएम तक जांच की मांग**

**राउरकेला:** राउरकेला महानगर निगम में विकास के नाम पर जारी कथित लूट-खसोट को लेकर एनसीपी (नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी) प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तीखे व्यंग्य करते हुए कहा कि "ओडिशा प्रशासन में संलिप्त बीजद संचालक वी.के. पांडियन के प्रतिनिधियों को सचिवालय बुलाकर जवाब तलब करना चाहिए।"

डॉ. यादव ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग से लेकर तेल खरीद, पुराने टेंडर को कमीशन के आधार पर नवीनिकरण और नवीन बाबू की योजनाओं के पट्ट व होर्डिंग्स की देखरेख तक – सब कुछ बीजद नेताओं के हित में चल रहा है। वहीं एनडीए सरकार की योजनाओं के होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है न ही प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है1

उन्होंने ट्वीट कर यह भी लिखा,

"एनडीए सरकार के ओडिशा मुखिया मोहन माझी के आउटसोर्शिंग को रोकने व वर्तमान सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के आदेशों को राउरकेला नगर निगम और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं।"

उन्होंने बीजद नेताओं पर आरोप लगाया कि सफाई, आपूर्ति, सुरक्षा, मानव संसाधन, वाहन और इंजीनियरिंग जैसे विभागों में पुरानी निविदाओं को ही लागू कर अवैध वसूली और पक्षपातपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

डॉ. यादव ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए ट्विटर पर #जांचहो और #कार्रवाईहो हैशटैग के साथ एक अभियान भी छेड़ दिया है ।राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। अब निगाहें शासन और प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं वहीं बीजद नेताओं व ठेकेदारों की भी घिग्गी बंध गई है1

# विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई 2025:- न्याय,जवाबदेही और मानव अधिकारों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है

**अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपराधियों के प्रत्यर्पण, आतंकवाद पनाहगार देशों का संज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करने की शक्तियां देना समय की मांग-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र**

वैश्विक स्तरपर एक दो दशक से जिस तरह संगठित अपराधोंकी संख्या में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय व स्थानीय समूह की गतिविधियों में वृद्धि हुई है इसे गंभीरता से रेखांकित करना समय की मांग है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि उनके संगठित अपराधों को अगर हम वर्तमान परिपेक्ष में देखें तो जांचएजेंसियों द्वारा आजकल अपराध की थ्योरी को अन्तर्राष्ट्रीय एंगल से जांच करने की थ्योरी भी अपनाई जाती है जिस तरह से वर्तमान में रूस- यूक्रेन इज़राइल हमास युद्ध,व अनेक देशों के स्थानीय लोकल स्तरोंपर मानवीय अधिकार हनन अपराध चर्चा में आ रहा है व विशेष रूप से युद्ध अपराध चर्चा में आया हैं, युद्ध अपराध के लिए विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय मानक मौजूद हैं, सहित अनेक केसों की तारें विदेशों तक जुड़ी हुई है। एक आपराधिक संगठन को हम गिरोह,माफिया, भीड़, सिंडीकेट, अंडरवर्ल्ड या गैंग्लैंड भी कह सकतें है, जिसमें अनेक अपराध जैसे सफेदपोश अपराध, वित्तीय अपराध, राजनीतिक अपराध, युद्ध के अपराध सहित अनेक परिभाषित अपराधों को शामिल किया जा सकता है जो अंतरराष्ट्रीय कनेक्टेड होते हैं इसीलिए आज हम ऐसे अपराधों और न्याय पर चर्चा करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में आते हैं उनके पीड़ितों को न्याय दिलाने, दुनियाँ भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर रोक लगाने विश्व को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से सचेत रहने के प्रति जागरूक करने के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध जानकारी के आधार पर अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई 2025 के उपलक्ष में इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे।

साथियों बात अगर हम आज की दुनिया में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 की प्रासंगिकता की करें तो (1) राजनीतिक संघर्षों, युद्ध अपराधों और असंख्य मानवाधिकार उल्लंघनों के इस युग में, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। (2)यह विश्वव्यापी स्तर पर एक पर्याप्त रूप से सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता की ओर ध्यानआकर्षित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए ज़िम्मेदार, बिना जवाबदेही के न बच सकें।(3) यूक्रेन, गाजा और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उभर रहे संकटों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो आम नागरिकों की रक्षा करता है और आगे होने वाले अत्याचारों को प्रभावी रूप से रोक सकता है।(4) यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) जैसी संस्थाओं और न्याय प्रशासन में राज्यों के बीच सहयोग के महत्व को भी उजागर करता है। (5) ऐसे युग में जहाँ बहुपक्षवाद और कानून के शासन को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह स्मरणोत्सव शांति, जवाबदेही और पीड़ितों के अधिकारों के प्रति वैश्विक निष्ठा की याद दिलाता है। (6) इसलिए

यह एक ऐसी न्यायपूर्ण दुनिया की दिशा में प्रेरणा देता है जहाँ न्याय सीमाओं और राजनीतिक हितों से परे जाकरसख़्ती से लागू हो।

साथियों बात अगर हम विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने के उद्देश्यों की करें तो, (1) विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसे बढ़ावा देना तथा दुनिया में सबसे गंभीर अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के विरुद्ध संघर्ष करना है (2) यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसे कानूनी तंत्रों के माध्यम से नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के कुख्यात अपराधियों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर बल देता है। (3) यह दिवस मानवाधिकारों की सुरक्षा, कानून के शासन को बनाए रखने और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।(4) इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहयोग और ठोस अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचों के माध्यम से एक अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष विश्व के निर्माण हेतु मिलकर काम करने की याद दिलाता है।

साथियों बात अगर हमअंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को समझने की करें तो- परिचय (1) यह विश्व का पहला स्थायी, स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है जो उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है जिन्होंने अत्यंत गंभीर अपराध किए हों। (2) इसमें चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को सम्मिलित किया गया है- नरसंहार युद्ध संबंधी अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध तथाआक्रामकता से संबंधित अपराध। (3) इस न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है और यह जुलाई 2002 से कार्य कर रहा है। (4) भारत ने अभी तक रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अतः वह आईसीसी का सदस्य नहीं है। (5) भारत का मानना है कि आईसीसी की कुछ धाराएं उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता, सैन्य कार्रवाई और आंतरिक सुरक्षा नीतियों के लिए बाधक हो सकती हैं। (6) भारत यह भी आशंका जताता हैकि आईसीसी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के वीटोयुक्त देशों का अत्यधिक प्रभाव है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के ढांचे की करें तो,संयुक्त राष्ट्र सेसंबंधित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। इस न्यायालय में 6 भाषाओं (अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज) में सुनवाई होती है, लेकिन काम अंग्रेजी और फ्रेंच में ही होता है। इसके सदस्य देशों की संख्या 123 है। 17 जुलाई 1998 को इसकी स्थापना हुई थी, इसने 1 जुलाई 2002 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया।

साथियों बात अगर हम न्यायालय की ज़रूरत की करें तो अपराध की दुनिया पर लगाम लगाने के लिए न्यायालय की जरूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व में न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी ।प्रतिवर्ष आज ही के दिन 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस भी कहा जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के प्रति जागरूक करना है।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के क्रियाकल्प की करें तो, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय एक स्थाई और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय और मानव अधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघन के आरोपियों को दंडित करने में सक्षम है। जिसमें नरसंहार का अपराध, अपराधों का युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराध शामिल है। अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय स्थापना तब हुई जब, राज्यों ने रोम में एक कानून को अपनाया इस की प्रतिमा को अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय के संविधि के रूप में जाना जाता है। आईसीसी राष्ट्रीय अदालतों की जगह नहीं लेता है। लेकिन यह तब उपलब्ध होता है जब कोई देश जांच करने में सक्षम नहीं होता और अपराधियों पर यह मुकदमा चला सकता है।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को अंतिम उपाय मानने की करें तो, अंतिम उपाय की अदालत के रूप में सेवा करने के इरादे से,आईसीसी मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिकप्रणालियों का पूरक है और अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालतें अनिच्छुक हों या अपराधियों पर मुकदमा चलाने में असमर्थ हों। इसमें सार्वभौमिक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है और यह केवल सदस्य राज्यों के भीतर किए गए अपराधों, सदस्य राज्यों के नागरिकों द्वारा किए गएअपराधों, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा न्यायालय को संदर्भित स्थितियों में अपराधों की जांच और मुकदमा चला सकता है ।

अतः अगर हम उपरोक्त विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई 2025:- न्याय जवाबदेही और मानव अधिकारों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक हैदुनियाँ की सरकारें प्रण करें:- अन्याय के नए रूपों को विफ़ल करेंगे, न्यायिक संस्थाओं को मज़बूत करेंगे वपीड़ितों को सशक्त बनाएंगे ।अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपराधियों के प्रत्यर्पण, आतंकवाद पनाहगार देशों का संज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करने की शक्तियां देना समय की मांग हैं।

# 2025 TVS Apache RTR 310 और भी ज्यादा हुई दमदार , नए फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

टीवीएस ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय नेकेड स्पोर्ट्स बाइक TVS Apache RTR 310 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। इसमें लॉन्च कंट्रोल की-लेस इग्निशन और मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट वाला 5-इंच TFT कंसोल जैसे नए फीचर्स हैं। बाइक नए रंग विकल्पों में भी उपलब्ध है। इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है इसमें वही 312cc का इंजन है।

**नई दिल्ली।** TVS ने अपनी पॉपलुर नेकेड स्पोर्ट्स बाइक Apache RTR 310 का अपडेटेड वर्जन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसे पहले के मुकाबले कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। इसमें लॉन्च कंट्रोल, की-लेस इग्निशन जैसे कई काम के और मजेदार फीचर्स शामिल हुए हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि 2025 TVS Apache RTR 310 को किन नए खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है।

**कितनी है कीमत ?**

| वेरिएंट | इंट्रोडक्टरी प्राइस | असल प्राइस |
|---|---|---|
| बेस वेरिएंट | 2,39,990 रुपये | 2,49,990 रुपये |
| टॉप वेरिएंट | 2,57,000 रुपये | 2,67,000 रुपये |
| BTO वेरिएंट | 2,75,000 रुपये | 2,85,000 रुपये |

सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार हैं तथा प्रारंभिक मूल्य सीमित अवधि के लिए मान्य है।

**क्या नया है ?**

पहले से ही TVS Apache RTR 310 कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ही आती है, लेकिन 2025 मॉडल में इसमें और भी बहुत कुछ जुड़ गया है। ये नए फीचर्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि काफी प्रैक्टिकल भी हैं।

नई Apache RTR 310 में बाइक को स्टैंडस्टिल से तेजी स्पीड देने के लिए लॉन्च कंट्रोल, डाउनशिफ्टिंग या ढलान पर बिना थ्रॉटल इनपुट के बाइक को ज्यादा स्मूद तरीके से कंट्रोल करने के लिए इंजन ब्रेकिंग सिस्टम, बाइक को दूर से ही स्टार्ट करने के लिए कीलेस इग्नीशन, मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट वाला अपडेटेड 5-इंच TFT कंसोल, ट्रांसपैरेंट क्लच कवर, बाइक को और स्पोर्टी लुक देने के लिए सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स दिए गए हैं।

बाइक को नए कलर ऑप्शन भी दिया गया है, जो Fiery Red, Arsenal Black, Fury Yellow और Sepang Blue। इसे पहले से ही Arsenal Black और Fury Yellow कलर में पेश किया जाता रहा है, लेकिन अब इनमें नए ग्राफिक्स दिए गए हैं। Sepang Blue कलर को केवल BTO वेरिएंट में लेकर आया गया है।

**क्या नहीं बदला ?**

TVS Apache RTR 310 का शार्प और अग्रेसिव लुक अब भी बरकरार है, जिसमें यूनिक स्प्लिट LED हेडलाइट है। क्लीन टेल सेक्शन है, जहां इंडिकेटर और नंबर प्लेट टायर हगर पर लगे हैं। Trellis फ्रेम भी वही है। 41mm इनवर्टेड फ्रंट फोर्क और प्रीलोड एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक मिलता है। BTO वेरिएंट में दोनों साइड KYB का फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है।300mm फ्रंट डिस्क और 240mm रियर डिस्क ब्रेक सेटअप मौजूद है। बाइक के दोनों सिरों पर 17-इंच अलॉय व्हील्स हैं, जिसमें फ्रंट में 110-सेक्शन और रियर में 150-सेक्शन के Michelin Road 5 टायर्स आते हैं।

**इन फीचर्स से है लैस**

TVS Apache RTR 310 में छह-एक्सिस IMU बेस्ड सिस्टम, Cornering डुअल चैनल ABS, लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन, पांच राइड मोड्स- Urban, Rain, SuperMoto, Sport, Track दिया गया है। इसके साथ ही TFT कंसोल पर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और SMS/कॉल अलर्ट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

**कैसा है इंजन ?**

TVS Apache RTR 310 के इंजन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 312cc सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 35.6PS की पावर और 28.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

# इलेक्ट्रिक वाहनों की धूम, वित्त वर्ष 28 तक 7% से अधिक होगी हिस्सेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

केयरएज एडवाइजरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कार बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 28 तक बढ़कर 7% से अधिक हो जाएगी। यह वृद्धि दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति नए मॉडलों के लॉन्च और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर निर्भर करेगी। वित्त वर्ष 25 में ईवी वाहनों की बिक्री 1.07 लाख इकाई हो गई है जो वित्त वर्ष 21 में 5000 इकाई से अधिक थी।

**नई दिल्ली:** देश के कार बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 28 तक बढ़कर सात प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। हालांकि, यह दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति, नए माडल के लांच और सरकार की ओर से देश में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए जाने पर निर्भर करेगा। केयरएज एडवाइजरी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का इलेक्ट्रिक कार ईकोसिस्टम बीते कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है। इस दौरान ईवी वाहनों की बिक्री बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 1.07 लाख इकाई हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 21 में 5,000 इकाई से अधिक थी।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में चार पहिया वाहनों की हिस्सेदारी काफी कम है। देश में बिकने वाले अधिकतर इलेक्ट्रिक वाहन दोपहिया और तिपहिया ही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2030 तक कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है और इसे लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेम-3, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम और कोबाल्ट, लिथियम-आयन वेस्ट और ग्रेफाइट सहित महत्वपूर्ण बैटरी मिनरल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करने से जैसी पहलों से वाहन उत्पादन लागत कम होने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में सुधार होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में मुताबिक, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अब तेजी से बढ़ रहा है। पिछले तीन वर्षों में, भारत में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ी है, जो कैलेंडर वर्ष 2022 में 5,151 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत तक 26,000 से अधिक हो गई है।

# महिंद्रा लेकर आई एक्सयूवी 3XO का नया वेरिएंट, बाकी ट्रिम से कितनी है अलग

महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर Mahindra XUV 3XO REVX का नया मिड-स्पेक वेरिएंट लॉन्च किया है। इसमें नई ग्रिल अलॉय व्हील्स इंटीरियर थीम और सीट अपहोल्स्ट्री जैसे बदलाव हैं। यह पांच रंगों में उपलब्ध है और इसमें 16 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं। इसमें डुअल 10.25-इंच स्क्रीन पैनोरमिक सनरूफ और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स हैं। सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग दिए गए हैं।

**नई दिल्ली।** महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर Mahindra XUV 3XO REVX के लिए नए मिड-स्पेक वेरिएंट को हाल ही में लॉन्च किया है। यह नए वेरिएंट पहले से मिल रही वेरिएंट्स की तुलना में कुछ खास बदलावों के साथ आते हैं, जैसे- नई ग्रिल, अलॉय व्हील्स, इंटीरियर थीम और सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं कि यह किन खास फीचर्स के साथ लेकर आई गई है।

**Mahindra XUV 3XO REVX का डिजाइन**

REVX A में बॉडी-कलर्ड ग्रिल दी गई है, जिसमें रेगुलर XUV 3XO जैसी ही क्रोम स्लैट्स हैं। इसमें LED DRLs के साथ वही प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स भी मिलती हैं। बंपर का निचला हिस्सा अभी भी ब्लैक आउट है जिसमें कुछ घुमावदार डिजाइन एलिमेंट्स हैं।

इसे पांच कलर में लेकर आया गया है, जो एवरेस्ट व्हाइट, गैलेक्सी ग्रे, नेबुला ब्लू, स्टील्थ ब्लैक और टैंगो रेड है। इसके स्टील्थ ब्लैक कलर में ग्रे ग्रिल मिलती है, जबकि बाकी कलर में बॉडी-कलर्ड फिनिश दिया गया है।

इसे साइड से देखने पर 16-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो नए वेरिएंट को रेगुलर ट्रिम्स से ज़्यादा स्पोर्टी बनाते हैं। इसे अलग दिखाने के लिए महिंद्रा ने C-पिलर पर REVX बैज जोड़ा है। इसके व्हील आर्च और दरवाजों पर ब्लैक बॉडी क्लैडिंग जारी है। इसके रूफ, रूफ रेल्स और A-, B-, C-पिलर भी काले रंग में फिनिश किए गए हैं। इसके पीछे की तरफ ही कनेक्टेड LED टेल लाइट्स और रिफ्लेक्टर और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ ब्लैक बंपर दिया गया है।

**Mahindra XUV 3XO REVX का इंटीरियर**

XUV 3XO के स्टैंडर्ड और REVX दोनों वेरिएंट में एक ही ब्लैक / व्हाइट डैशबोर्ड दिया गया है। इसके अलावा, डैशबोर्ड पर डुअल 10.25-इंच स्क्रीन और 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिए गए हैं। बाकी चीजें पहले की तरह ही है।

# एप्रीला ने भारत में लॉन्च किए दो नए स्कूटर, प्रीमियम फीचर्स और दमदार इंजन से है लैस

अप्रिलिया इंडिया ने भारत में Aprilia SR 125 hp.e और Aprilia SR 175 hp.e स्कूटर लॉन्च किए हैं। SR 175 में बड़ा इंजन है और दोनों स्कूटर अपडेटेड कंसोल नए रंग और आधुनिक फीचर्स के साथ आते हैं। SR 125 hp.e में 124.45 cc का इंजन है जबकि SR 175 hp.e में 174.7cc का इंजन है। दोनों में कनेक्टिविटी फीचर्स और TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल है।

**नई दिल्ली।** अप्रिलिया इंडिया ने भारत में अपने दो नए स्कूटर Aprilia SR 125 hp.e और Aprilia SR 175 hp.e को लॉन्च किया है। दोनों ही स्कूटर को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। SR 175 में बड़े इंजन के अलावा, दोनों स्कूटरों को अपडेटेड कंसोल, नई कलर स्कीम और कई आधुनिक फीचर्स के साथ भारत में लेकर आया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि अप्रिलिया की इन दोनों स्कूटर को किन फीचर्स के साथ लेकर आया गया है।

भारत में Aprilia SR 125 hp.e को 1,21,480 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। इसका डिजाइन काफी हद तक रेगुलर Aprilia SR 125 जैसा ही है, लेकिन बॉडी पैनल्स पर हल्के नए ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसे तीन नए कलर ऑप्शन मैट ब्लैक, ग्लॉसी माज़्दा ग्रे + मैट ब्लैक, और ग्लॉसी रेड + मैट ब्लैक में लेकर आया गया है।

इसमें 124.45 cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 10.60 PS की पावर और 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

इसमें 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें कॉल और SMS अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और राइड स्टैट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही ऑल-LED लाइटिंग सेटअप और CBS (कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड तौर पर दिया जा रहा है।

भारतीय बाजार में Aprilia SR 125 hp.e का मुकाबला TVS NTorq 125 और Suzuki Avenis 125 से देखने के लिए मिलेगा।

यह बिल्कुल ही नया मॉडल है, लेकिन यह स्कूटर काफी हद तक Aprilia SR 160 जैसा ही दिखाता है। इसके डिजाइन में हल्के बदलाव किए गए हैं। इसे दो कलर ऑप्शन में लेकर आया गया है, जो मैट प्रिजमैटिक डार्क और ग्लॉसी टेक व्हाइट है।

Aprilia SR 175 hp.e में 174.7cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 13.26 PS की पावर और 14.14 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

इस स्कूटर में 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल और कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक दिया गया है। इसमें सिंगल-चैनल ABS के साथ फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है।

# परीक्षा प्रणाली या 'सामाजिक भ्रमजाल ?

विजय गर्ग

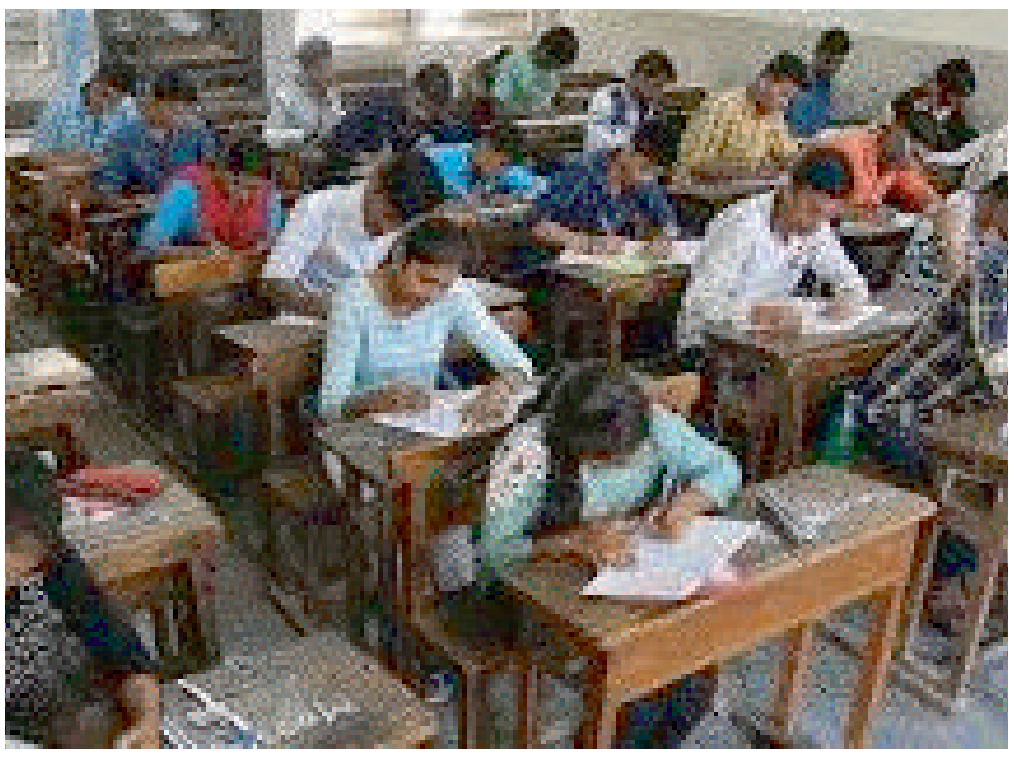



शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला कहा गया है। यह व्यक्ति के ज्ञान, विवेक, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व विकास का माध्यम रही है। लेकिन आज की तारीख में यह उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया है। शिक्षा अब एक 'अंक- उद्योग' में तब्दील हो चुकी है, जहां ज्ञान की बजाय नंबर ही सफलता का पर्याय बन गए हैं। अब यह न तो चरित्र निर्माण का साधन रही, न ही सामाजिक चेतना का उपकरण। यह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अंक दौड़ की एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में धकेलने वाला शोषण तंत्र बन गई है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में इस बार 45,516 छात्रों ने 95 फीसदी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, जो कुल परीक्षार्थियों का लगभग 1.92 प्रतिशत है। वहीं 1,99,944 छात्रों ने 90 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए, जो 8.43 प्रतिशत के करीब है। यह कोई अपवाद नहीं है हर साल यह आंकड़ा और ऊपर जा रहा है। लेकिन जब इन अंकों की असलियत जानने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले शिक्षकों की कार्यप्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो व्यवस्था मौन हो जाती है। यह एक साजिशन खड़ा किया गया भ्रमजाल है, जो शिक्षा को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बजाय एक कृत्रिम दौड़ में तब्दील कर रहा है।

शिक्षा के इस व्यवसायीकरण की गहराई को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस ढांचे को देखें जिसमें यह सब संचालित हो रहा है। 2019 में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कुल 22,030 स्कूलों में से लगभग 80 प्रतिशत स्कूल निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस आंकड़े में केवल 1,138 केंद्रीय विद्यालय, 2,727 सरकारी स्कूल, 598 नवोदय विद्यालय और 14 तिब्बती स्कूल शामिल हैं, जबकि शेष 17,553 निजी स्कूल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा निजीकरण के दबाव में है, जहां शिक्षा की गुणवत्ता नहीं, बल्कि परिणामों की संख्या मायने रखती है और जब यही 'अंकवीर' छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, जेईई या नीट में पहुंचते हैं, तो उनकी वास्तविक योग्यता सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में लगभग 11.35 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से मात्र 11,474 छात्र ही मुख्य परीक्षा तक पहुंच सके। यही हाल साल 2024 का रहा। इस वर्ष लगभग 13.4 लाख छात्रों में से सिर्फ 14,627 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा तक पहुंचे। यानि बोर्ड परीक्षा के हाई स्कोरर प्रीलिम्स की पहली कसौटी पर ही फेल हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि बोर्ड परीक्षाओं में मिलने वाले ऊंचे अंक असल में बौद्धिक क्षमता या विषय की समझ का पैमाना नहीं हैं। यह मूल्यांकन प्रणाली रटंत विद्या तयशुदा उत्तरों और सजावटी भाषा पर आधारित है, जिसमें मौलिक सोच और विश्लेषण की कोई जगह नहीं।

यह समस्या केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिकता पूरे उत्तर भारत के शैक्षणिक वातावरण में व्याप्त है। स्कूलों में अब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि अच्छे परिणामों के जरिए स्कूल का नाम रौशन करना बन गया है। इसके उलट, दक्षिण भारत की तस्वीर अपेक्षाकृत बेहतर है। वहां के माता- पिता शिक्षा को केवल अंक पाने के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और कौशल निर्माण के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्र राष्ट्रीय परीक्षाओं में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वहां की शिक्षा प्रणाली में केवल परीक्षाफल नहीं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहारिकता और नवाचार को भी महत्व दिया जाता है। उत्तर भारत के अधिकतर स्कूलों में शिक्षण अब गाइडबुक, मॉडल पेपर और स्मार्ट आंसर पर आधारित हो गया है। शिक्षक भी केवल परिणाम उन्मुख होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके मूल्यांकन का आधार भी अब बच्चों के अंक बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। नंबर की होड़ में बच्चों में अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, हीन भावना और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। शिक्षा अब ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि एक दौड़ बन गई है, जिसमें सबसे तेज दौड़ने वाला ही विजेता माना जाता है।

*विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब*

# विज्ञान से छंटेगा अंधविश्वास का अंधियारा

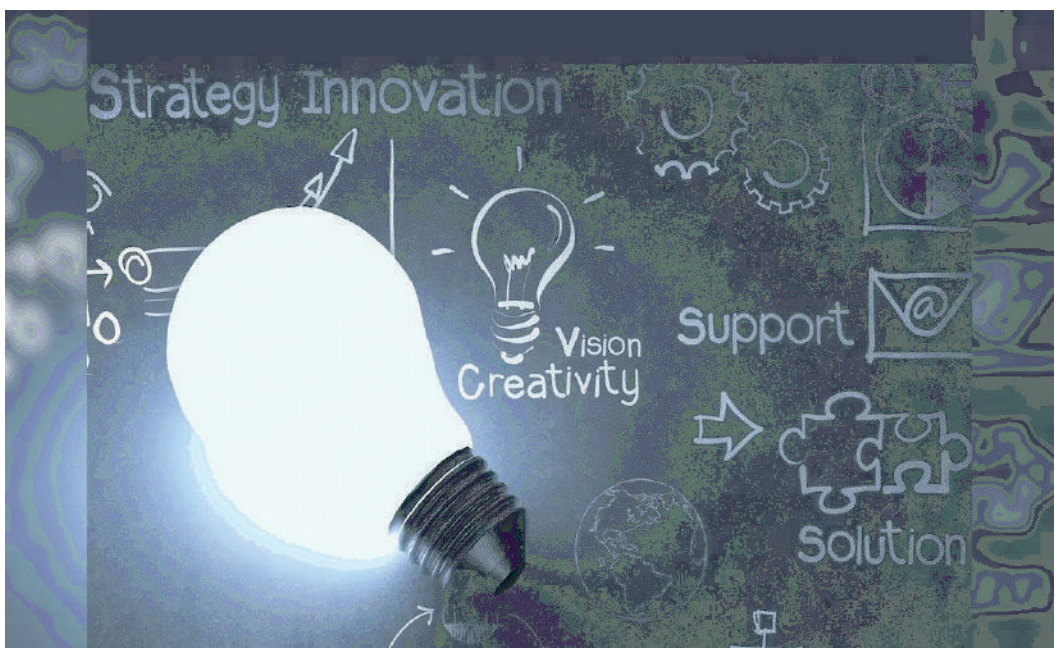




विजय गर्ग

बिहार में पूर्णिया जिले के एक गांव टेटगामा में अंधविश्वास में अंधी भीड़ ने पांच निर्दोष जिंदगियों को निगल लिया। 'डायन' करार देकर एक ही परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया गया। यह घटना केवल एक वीभत्स अपराध नहीं, बल्कि हमारे समाज में गहराई तक जड़ जमाए अंधविश्वास, तंत्र-मंत्र और रूढ़िवादी मान्यताओं की डरावनी तस्वीर है, जो बताती है कि वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक चेतना के बीच अब भी एक बहुत बड़ी खाई मौजूद है।

आज जबकि विज्ञान ने हमें अति उन्नत प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष यात्रा, बायो इंजीनियरिंग और एआइ जैसे क्षेत्रों में पहुंचा दिया है, वहीं दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा तबका अभी भी नींबू- मिर्ची, पुनर्जन्म और भूत-प्रेत जैसी बातों में यकीन करता है। यह विसंगति केवल अशिक्षित वर्ग में ही नहीं है। इसकी जड़ें हमारी सामाजिक संरचना में छिपी हैं, जहां वैज्ञानिक नजरिए को पर्याप्त तवज्जो नहीं दिया जाता। आजादी के बाद वैज्ञानिक नजरिए को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थान और योजनाएं बनीं, किंतु वे समाज के सोच को बदलने में असफल रहीं। जिन तबकों को शिक्षा और समृद्धि नहीं मिली, वे चमत्कारों की आशा में अंधविश्वासों में चिपके रहे। और जिनमें समृद्धि आई, वे उसे खोने के डर से इन्हीं कुरीतियों का अनुसरण करते रहे।

दरअसल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन को तर्क, प्रमाण और विवेक के साथ समझने का तरीका है। यह नजरिया हमें सिखाता है कि किसी बात को तभी स्वीकारें जब उसके पक्ष में साक्ष्य हो। लेकिन हमारे समाज में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के बजाय उसका दमन किया जाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक नजरिए का अभाव सामाजिक जीवन को दिशाहीन बनाए हुए है। संविधान ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नागरिक का मौलिक कर्तव्य घोषित किया है। इसके बावजूद भारतीय विज्ञान कांग्रेस जैसे मंचों पर छद्म-वैज्ञानिक दावों की प्रस्तुति, मीडिया में तर्कहीन विचारों का प्रचार व समाज में पाखंडियों की स्वीकृति यह दर्शाती है कि वैज्ञानिक दृष्टि हमारे समाज की मुख्यधारा नहीं बन सकी है।

इसलिए आज जरूरत है सामाजिक जागरूकता की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार की और यह समझने की कि जब हम विज्ञान को केवल तकनीकी लाभों तक सीमित रखते हैं और सोचने की स्वतंत्रता के रूप में नहीं अपनाते, तो हम विकास के नाम पर अंधेरे की ओर बढ़ते हैं। यह अंधेरा ही है, जिसने टेटगामा जैसे गांवों को आज भी 21वीं सदी के उजाले से दूर रखा है। हमें यह मानना ही होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही वह रोशनी है, जो अंधविश्वास के इस अंधेरे से समाज को बाहर निकाल सकती है। जब तक हम अपने सोचने के ढंग को नहीं बदलते, तब तक ऐसी घटनाएं हमारे विकास की सच्चाई को कठघरे में खड़ा करती रहेंगी।

*सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब*

# सोशल मीडियाको निरंकुश नहीं आजादी

विजय गर्ग

कथित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति के चलते उपजी विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश की जरूरत बताते हुए देश की शीर्ष अदालत ने आत्म-नियमन की जरूरत बतायी है। दरअसल, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ, एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिस पर धर्म विशेष के देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के चलते कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत का कहना था कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का मूल्य समझना चाहिए। साथ ही इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आत्म-संयम बरतना चाहिए। कोर्ट ने चेताया है कि यदि सोशल मीडिया पर विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगता तो सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। जो एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। निस्संदेह, समाज में विद्वेष व नफरत फैलाने वाले संदेश समरसता के भारतीय परिवेश के लिये गंभीर चुनौती बने हुए हैं। यही वजह है कि कोर्ट को कहना पड़ा कि वह नियमन के लिये दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। दरअसल, अदालत का मानना था कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत मिली आजादी असीमित कदापि नहीं है। यदि उससे सामाजिक समरसता में खलल पड़ता है तो सरकार को दखल देने का मौका मिलता है। जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिये अच्छा संकेत नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को सरकार नियंत्रित करे। सही मायनों में लोगों को समझना चाहिए कि देश की एकता व अखंडता बनाये रखना मौलिक कर्तव्य ही है। अदालत ने इस बाबत सवाल भी किया कि नागरिक स्वयं को संयमित क्यों नहीं कर सकते? कोर्ट का मानना था कि लोग तभी अभिव्यक्ति की आजादी का आनन्द ले सकते हैं जब यह संयमित ढंग से व्यक्त की जाए। शीर्ष अदालत की पीठ का मानना था कि नागरिकों के बीच भाईचारा होना चाहिए, तभी समाज में नफरत से मुकाबला किया जा सकता है। तभी हम गंगा-जमुनी संस्कृति के समाज का निर्माण कर सकते हैं।

वैसे कई राज्यों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के नियमन को लेकर सरकारी कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कई जगह विचारों की अभिव्यक्ति व कार्टून आदि बनाने को राजनीतिक दुराग्रह बताते हुए लोगों को गिरफ्तार तक किया गया है। जिसे सत्ताधीशों द्वारा बदले की भावना से की कार्रवाई बताया जाता रहा है। आरोप लगाया जाता रहा है कि सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के अनुरूप अमर्यादित अभिव्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन दूसरे राज्य में अन्य राजनीतिक दल की सरकार में यही अभिव्यक्ति अपराध बन जाती है। कहा जाता रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी द्वारा किसी मर्यादा को भंग करना घटिया या आपत्तिजनक तो हो सकता है लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। इसे कानून के आलोक में देखा जाना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों द्वारा सोशल मीडिया मंच का जमकर दुरुपयोग किया जाता रहा है। वहीं लोगों का कसूर यह है कि दल विशेष के एजेंडे वाली सामग्री को वे बिना पढ़े, दूसरे लोगों व समूहों में शेयर कर देते हैं। दरअसल, आम नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उनका संयमित व्यवहार कैसा होना चाहिए। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही सामग्री की कितनी संवेदनशीलता है। कई लोग जाने-अनजाने में ऐसी सामग्री दूसरे व्यक्तियों व समूहों में शेयर कर देते हैं जो समाज विरोधी हो सकती है। दरअसल, वे उसकी मूल सामग्री को बनाने वाले के छिपे एजेंडे को नहीं भांप पाते। कभी-कभी भावावेश में लोग ऐसे कदम उठा देते हैं। निस्संदेह, कोई भी व्यक्ति भावनात्मक दुर्बलताओं से मुक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे शेयर की जा रही सामग्री की तार्किकता पर मंथन जरूर करना चाहिए। दरअसल, सोशल मीडिया आज एक ऐसा अस्त्र बन गया है जो जरा सी चूक से घातक साबित हो सकता है। वास्तव में हर नागरिक को इतना सचेत व जागरूक होना जरूरी है कि वह विभिन्न स्रोतों से आने वाली सामग्री से जुड़ी मंशा को समझ सके। निस्संदेह, संयमित, तार्किक व सतर्क प्रतिक्रिया से हम अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का आनन्द ले सकते हैं।

*सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब*

# मातृभाषा में शिक्षण से साक्षरता व शिक्षा की गुणवत्ता में आशातीत बदलाव लाया जा सकता है

विजय गर्ग

भले ही जनाधार खोते राजनेता नई शिक्षा नीति के तीन भाषा फॉर्मूले का विरोध अपनी राजनीति चमकाने के लिये कर रहे हों, लेकिन इस दिशा में किए गए नये प्रयोग आशा की नई किरण भी जगा रहे हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में जितनी आसानी और सहजता से सीख सकता है, उतना किसी थोपी गई भाषा में नहीं। तमाम शिक्षाविद् और भाषाविज्ञानी मानते रहे हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले शब्दों व परिवेशगत ज्ञान विद्यार्थियों को जल्दी सीखने में मददगार हो सकता है। देश में 121 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं मातृभाषाओं की संख्या सोलह से अधिक है। इतनी अधिक भाषायी विविधता वाले देश में, जब बच्चे अपने आसपास जो देखते और महसूस करते हैं, वो उनकी स्मृतियों में स्थायी बस जाते हैं। जब ये बातें उनके शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनती हैं, तो वे इसका आसानी से अंगीकार कर लेते हैं। कई शिक्षा आयोगों ने भी इसी बात की वकालत की है। इसी सोच के चलते देश के विभिन्न भागों में तीन भाषा फॉर्मूले को लेकर कई प्रयोग हो रहे हैं। इस रचनात्मक पहल के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। जिसके निष्कर्ष बताते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाई करने से बच्चों की सीखने की गति तेज हुई है। इससे साक्षरता की दर में सकारात्मक बदलाव आया है। इतना ही नहीं इससे जहां छात्र-छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं उनकी कक्षा में सहभागिता भी बढ़ी है। सही मायनों में नई शिक्षा नीति में तीन भाषा फॉर्मूले का मकसद भी यही रहा है। विगत के अनुभव बताते हैं कि जब छात्र-छात्राओं को उनकी मातृभाषा से इतर अन्य भाषा में पढ़ाया जाता रहा है तो इसका असर उनकी सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। ऐसे में दूर-दराज के गांव-देहात या आदिवासी इलाकों से आने वाले विद्यार्थी अन्य शहरी बच्चों का मुकाबले करने में असफल हो जाते हैं। जिससे उनके स्कूल छोड़ने के प्रतिशत में भी वृद्धि होती है।

मौजूदा स्थितियों में तीन भाषा फॉर्मूले को लेकर किए जा रहे नये प्रयोग नई उम्मीद जगा रहे हैं। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउडेंशन ने छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और ओडिशा के 13 जिलों में बच्चों को उनकी राज्यभाषा और अंग्रेजी के साथ-साथ मातृभाषा में पढ़ाने के लिये राज्य सरकारों के साथ मिलकर बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। इससे न केवल चयनित जिलों में बच्चों की साक्षरता दर में सुधार हुआ, बल्कि उनमें अन्य भाषा को सीखने की अभिरुचि भी बढ़ी है। एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में प्रारंभिक कक्षाओं में स्थानीय भाषा, सांस्कृतिक परंपराओं व परंपरागता ज्ञान को शामिल करने के लिये स्थानीय समुदायों की मदद भी ली गई। जिसमें स्थानीय परिवेश में उपजी लोककथाओं, स्थानीय संस्कृति आधारित कहानियां तथा कई पीढ़ियों से हासिल पारंपरिक ज्ञान को भी शामिल किया गया। बच्चों की पढ़ाई में रुचि बनी रहे, इसके लिये रचनाधर्मिता का सहारा भी लिया गया। जिसमें मौखिक शिक्षा प्रणाली का भी उपयोग किया गया। ऐसी शिक्षण सामग्री तैयार की गई जिससे बच्चे आसानी व रुचि के साथ आसानी से सीख सकें। मसलन कविता पोस्टर, कहानी के पात्रों के चित्र, वार्तालाप दर्शाने वाले चार्ट, शब्द कार्ड, वर्ण मात्रा कार्ड तथा चित्रों के जरिये कहानी बताने वाली किताबें इसमें शामिल की गईं। जिसने छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि जगायी और वे आसानी से सीखने लगे। उदाहरण के लिये छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जहां पचास फीसदी बच्चे हल्बी बोलते थे, वहां हिंदी में पढ़ाई करने से शिक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहे थे। इस क्षेत्र में प्रारंभिक कक्षाओं में हल्बी को हिंदी के साथ जोड़कर पढ़ाया गया। इस शैक्षिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बाद सर्वे में यह सामने आया कि बस्तर में औसतन साक्षरता की दर में इकतीस फीसदी की, संख्या ज्ञान में पच्चीस फीसदी और वर्ण-अक्षर पहचान में छब्बीस फीसदी का सुधार हुआ। इसके अलावा मौखिक पाठन में चौदह फीसदी का सुधार आया। निश्चित रूप से इस अभिनव पहल ने देश को संदेश दिया कि मातृभाषा में शिक्षण से साक्षरता व शिक्षा की गुणवत्ता में आशातीत बदलाव लाया जा सकता है।

**सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब**

# महिलाओं द्वारा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद क्या होता है

विजय गर्ग

महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, भारतीय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी खतरनाक रूप से कम है। महिला सशक्तिकरण सिद्धांतों के अनुसार, भारत में महिला साक्षरता 77 प्रतिशत को पार कर गई है, और महिलाओं के पास अब 48 प्रतिशत उच्च शिक्षा नामांकन है। फिर भी, महिला श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 में सिर्फ 41.7 प्रतिशत थी - जो वैश्विक औसत से काफी नीचे थी। यह स्टार्क असमानता शैक्षिक प्राप्ति और वास्तविक रोजगार परिणामों के बीच एक परेशान डिस्कनेक्ट को प्रकट करती है।

असली मुद्दा यह है कि महिलाओं द्वारा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद क्या होता है। जबकि कॉलेज और विश्वविद्यालय गर्व से बढ़ती महिला नामांकन को उजागर करते हैं, कुछ ट्रैक या समर्थन करते हैं कि इनमें से कितनी महिलाएं औपचारिक नौकरियों, उद्यमिता या नेतृत्व भूमिकाओं में संक्रमण करती हैं। यह निरीक्षण देश की लगभग आधी आबादी की उत्पादक क्षमता को कम करता है।

WEP डेटा के अनुसार, केवल 20 प्रतिशत अकादमिक रूप से मजबूत महिला स्नातक औपचारिक कार्यबल में प्रवेश करते हैं या व्यवसाय शुरू करते हैं। स्पष्ट रूप से, अकेले योग्यता पर्याप्त नहीं है - महिलाओं को अपनी पेशेवर यात्रा में अगला कदम उठाने में मदद करने के लिए अधिक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र की एक दबाव की आवश्यकता है।

एक व्यावहारिक और प्रभावशाली समाधान



एक ₹रूपांतरण दर₹ को शामिल करना है - छात्रों का प्रतिशत, विशेष रूप से महिलाएं, जो शिक्षा से रोजगार या उद्यमिता में संक्रमण करती हैं - राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में।

इसे संस्थागत रैंकिंग में एकीकृत करके, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को शिक्षाविदों से आगे बढ़ने और वास्तविक दुनिया के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह महिलाओं को स्वीकार करने और शिक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है; संस्थानों को कार्यबल में अपनी सफलता को भी सक्षम करना चाहिए।

इस संक्रमण अंतर को पाटने के लिए, शिक्षण संस्थानों को संरचित कैरियर परामर्श, उद्यमिता प्रशिक्षण और मेंटरशिप कार्यक्रमों की पेशकश करनी चाहिए।

विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिज़ाइन किए गए नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम आत्मविश्वास बनाने, सामुदायिक-निर्माण कौशल विकसित करने और महत्वाकांक्षा का पोषण करने में मदद कर सकते हैं - उन्हें प्रभावशाली भूमिकाओं को लेने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए लैस कर सकते हैं।

हालांकि एफएलएफपीआर ने हाल के वर्षों में थोड़ी तेजी दिखाई है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा स्वरोजगार या अवैतनिक परिवार के काम से आता है, खासकर ग्रामीण भारत में। रोजगार के ये रूप अक्सर अस्थिर होते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देते हैं।

शहरी सेटिंग्स में, जबकि महिलाओं के पास प्रवेश स्तर की 31 प्रतिशत नौकरियां हैं, उनका प्रतिनिधित्व नाटकीय रूप से नेतृत्व की भूमिकाओं में सिर्फ 13 प्रतिशत तक गिर जाता है। यह लिंग असंतुलन न केवल गहरी जड़ें वाले संरचनात्मक मुद्दों को दर्शाता है, बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा या विक्सिट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवरोध भी है।

शोध से पता चलता है कि रोजगार में लिंग अंतर को बंद करने से भारत की जीडीपी में 770 बिलियन डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे देश की प्रगति में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में काफी तेजी आ सकती है।

महिलाओं के लिए समान कार्यबल भागीदारी सुनिश्चित करना केवल निष्पक्षता का विषय नहीं है - यह एक रणनीतिक आर्थिक अनिवार्यता है। यह जवाबदेही का समय है। शिक्षण संस्थानों को न केवल सम्मानित डिग्री के लिए, बल्कि अपने स्नातकों के वास्तविक जीवन के परिणामों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

एनआईआरएफ रैंकिंग में रूपांतरण दरों को शामिल करके, हम उच्च शिक्षा परिदृश्य को एक में फिर से आकार देना शुरू कर सकते हैं जो सक्रिय रूप से महिलाओं को कार्यबल में सफल होने का अधिकार देता है। यह केवल एक नीति अनुशंसा नहीं है - यह कार्रवाई के लिए एक कॉल है।

यदि संस्थान और अधिकारी इस दृष्टि से अपने लक्ष्यों को संरेखित करते हैं, तो 'महिला सशक्तीकरण' एक नारा होने से एक औसत दर्जे की वास्तविकता की ओर बढ़ेगा। भारत का आर्थिक इंजन अब अपनी आधी क्षमता पर चलने का जोखिम नहीं उठा सकता है। समावेशी विकास की यात्रा शुरू होती है जहां करियर शुरू होता है: हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में।

**निष्कर्ष**

भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है जहां कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाना केवल एक नैतिक अनिवार्यता नहीं बल्कि एक रणनीतिक आर्थिक आवश्यकता है।

कैरियर परामर्श, उद्यमिता समर्थन और नेतृत्व प्रशिक्षण की पेशकश करके, कॉलेज परिवर्तन के सच्चे उत्प्रेरक बन सकते हैं।

*सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब*

# तनाव में शरीर के अंग करते हैं आपस में संवाद

विजय गर्ग

एक नए अध्ययन ने यह दिखाया है कि शारीरिक तनाव मसलन व्यायाम या नींद की कमी के दौरान शरीर के विभिन्न अंग एक-दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं? शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे किसी बीमारी का पहले निदान करने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, जर्नल आफ फिजियोलाजी में प्रकाशित यह अध्ययन सम्पूर्ण शरीर के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है बजाय इसके कि हृदय या श्वसन दर जैसे अलग-अलग मापों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

पोट्रसमाउथ विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी कालेज लंदन के शोधकर्ताओं बताया कि ट्रांसफर एंट्रापी' (शरीर के संकेतों की निगरानी की एक विधि) का उपयोग करते हुए मानचित्रों का एक नेटवर्क बनाया गया जो यह दर्शाता है कि तनाव की स्थिति में शरीर के कौन से अंग 'सूचना केंद्र' के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए व्यायाम के दौरान हृदय मांसपेशियों में रक्त प्रवाहित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होता है। उस समय यह अन्य अंगों से सबसे अधिक इनपुट प्राप्त करता है इसलिए यह शरीर को व्यायाम के अनुकूल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाता है।

एसोसिएट प्रोफेसर और नेटवर्क फिजियोलाजी लैब के प्रमुख अलीरेजा मनी ने बताया कि अध्ययन के दौरान तीन तनावपूर्ण वातावरणों जैसे कम आक्सीजन (हाइपोक्सिया), नींद की कमी और शारीरिक मध्यम तीव्रता के व्यायाम (साइकिलिंग) के दौरान पहनने योग्य सेंसर का उपयोग करके शरीर की स्थिति मानीटर की गई। एक फेस मास्क ने



प्रतिभागियों की श्वसन गैसों को मापा जबकि एक पल्स आक्सीमीटर ने ब्लड आक्सीजन स्तरों को ट्रैक किया। इसके बाद रिकार्ड किए गए संकेतों का विश्लेषण किया कि अंग प्रणालियों के बीच जानकारी कैसे स्थानांतरित हो रही थी। लेखकों ने लिखा, ₹व्यायाम के दौरान, हृदय दर सूचना का प्राथमिक प्राप्तकर्ता बनकर उभरी जबकि ब्लड आक्सीजन ने मुख्य प्रसारक के रूप में कार्य किया। हाइपोक्सिया ने नेटवर्क में ब्लड आक्सीजन को एक केंद्र के रूप में संलग्न किया।₹ उन्होंने कहा कि हमारा शरीर एक समय में केवल एक ही चीज पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह एकीकृत तरीके से और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया दे रहा होता है। इसका मानचित्र बनाकर हम सीख रहे हैं कि सामान्य पैटर्न कैसा दिखता है ताकि हम यह पता लगा सकें कि कब चीजें गलत हो रही हैं।

*सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट*

# भारत स्पेस से निडर, कॉन्फिडेंट और गर्व से पूर्ण !



भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर सकुशल वापसी हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। उनकी धरती पर सकुशल वापसी यह दिखाती है कि यदि मन में विश्वास, दृढ़ संकल्प, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, समर्पण, साहस और जज्बा हो तो उसे सफलता जरूर हासिल होती है। शुभांशु 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पर लौटे हैं और उन्होंने करोड़ों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। कहना ग़लत नहीं होगा कि अंतरिक्ष में विभिन्न अध्ययनों के बाद शुभांशु की धरती पर वापसी भारत के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। शुभांशु शुक्ला और एक्सिओम-4 मिशन के तीन अन्य अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आइएसएस) से धरती पर लौटे तो यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण बन गया।शुभांशु व तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के इस मिशन की कामयाबी के लिए हम सब लगातार दुआएं मांग रहे थे, क्योंकि हमने यह देखा था कि किस प्रकार से सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को नौ महीने तक अंतरिक्ष में रुकना पड़ा था। उसके कारण इस मिशन को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं हमारे मन में थीं। वास्तव में, इस मिशन के लिए इसरो, नासा के साथ ही उनके वैज्ञानिक और तकनीशियन भूरि-भूरि प्रशंसा के हकदार हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन से कामयाबी के शिखर को छुआ है। आज मानव अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, और इस मिशन ने मनुष्य सामर्थ्य का एक नया अध्याय खोलकर मानवता के समक्ष रख दिया है। कहना ग़लत नहीं होगा कि भारतीय अंतरिक्ष अभियानों के लिए यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। भारत के लिए यह पल उपलब्धियों भरा इसलिए भी है, क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा था। जिस ग्रेस यान से शुभांशु तीन अन्य सहयात्रियों के साथ धरती पर लौटे, वह 580 पाउंड (लगभग 263 किलोग्राम) सामान लेकर लौटा है, जिसमें नासा का हार्डवेयर, प्रयोगों का डेटा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आइएसएस) का कुछ कचरा शामिल है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी कि आइएसएस पर अपने प्रवास के दौरान शुभांशु ने कुछ ऐसे सैम्पल भी लिए हैं, जो भविष्य में बड़े अंतरिक्ष अभियानों के लिए भोजन, बॉयोफ्यूल व ऑक्सीजन का स्रोत बन सकते हैं। पाठकों को बताता चलूं कि अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार से वातावरण के साथ सामंजस्य और तालमेल बिठाते हैं तथा अंतरिक्ष में रहकर वो कैसा महसूस करते हैं, वह भी इस मिशन में (एक्सिओम-4 मिशन) रिसर्च का विषय रहा है, जिसका फायदा अंतरिक्ष यात्रियों को भविष्य में मिलेगा।चाहे पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाना हो अथवा अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लौटना हो, दोनों ही प्रक्रियाएं बहुत ही जटिल होतीं हैं, तथा जिसमें बाधाएं आने का खतरा सदैव बना रहता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि स्पेसक्राफ्ट का आइएसएस से जुड़ना जितना जटिल है उतना ही जटिल उससे अलग होना भी है। वैसे भी जब भी कोई वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो गुरुत्वाकर्षण (ग्रेविटी) और प्रतिरोध (रेसिस्टेंस) समेत कुछ दूसरे बल भी काम करते हैं, ऐसे में बहुत दिक्कतें आतीं हैं। निश्चित ही यह मिशन भारत को अंतरिक्ष, विज्ञान के क्षेत्र में और तकनीक के क्षेत्र में नई उपलब्धियां दिलाने वाला साबित होगा और इससे अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स को निश्चित ही मजबूती भी मिल सकेगी।सच तो यह है कि इस मिशन से भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती भूमिका को मजबूती व एक नई दिशा मिली है। हमने संपूर्ण विश्व के समक्ष यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम वैश्विक स्तर पर एक सिरमौर देश बनने जा रहे हैं। हमने इससे पूर्व भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में चांद पर उतरकर, सूर्य मिशन व अन्य मिशनों में अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। अगले लगभग हफ्ते के एकांतवास के बाद शुभांशु आम लोगों के बीच आएंगे और इसरो के वैज्ञानिक उनके प्रयोगों-अनुभवों से अंतरिक्ष में आगे की राह तलाशेंगे। हाल फिलहाल पाठकों को बताता चलूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इस अभियान के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये का योगदान किया है। उसकी भविष्य की योजनाओं में इस अभियान से अर्जित विभिन्न तथ्य व सूचनाएं बेहद कारगर साबित होने वाले हैं।शुभांशु ने अंतरिक्ष में रहकर साठ से ज्यादा प्रयोग किए, जिनमें माइक्रोग्रैविटी में जैविक प्रक्रियाओं, रेडिएशन के प्रभाव, और मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों का अध्ययन शामिल था। वास्तव में, इन प्रयोगों से हासिल हुआ डेटा न सिर्फ गगनयान मिशन के लिए अहम है, बल्कि यह मेडिकल साइंस, खास तौर पर ब्लड ग्लूकोज प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी योगदान देगा और यह भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए उपयोगी होगा। शुभांशु ने आईएसएस पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी अनुभव हासिल किए हैं। एक्सियम स्पेस के अनुसार, उन्होंने 'वॉयेजर डिस्प्ले' अध्ययन में हिस्सा लिया। इस स्टडी के जरिए यह समझा जाना था कि स्पेस में लंबे वक्त तक कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहने से आंखों पर और हैंड-आई को-ऑर्डिनेशन पर क्या असर पड़ता है।इसके अलावा शुभांशु ने इस सफर पर 'अक्वायर्ड इक्विवेलेंस टेस्ट' के जरिए से अंतरिक्ष में सीखने और अनुकूलन की क्षमता का अध्ययन भी किया गया। पाठकों को बताता चलूं कि इस मिशन पर रेड नैनो डोजीमीटर जैसे उपकरणों का उपयोग कर रेडिएशन के प्रभावों की निगरानी की गई, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए अहम है। इतना ही नहीं, शुभांशु ने मेथी और मूंग की खेती जैसे प्रयोग भी किए, जो अंतरिक्ष में खाना उगाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर यह बात कही जा सकती है कि शुभांशु की इस अंतरिक्ष यात्रा से विशेषकर हमारे देश के 'गगनयान अभियान' को इससे बहुत बल मिलेगा और इस बात को स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेखांकित किया है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। अंत में यही कहूंगा कि शुमांशु की यह अंतरिक्ष यात्रा भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। न सिर्फ शुभांशु राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, बल्कि वह आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय भी हैं। स्वयं शुभांशु के शब्दों में 'आज का भारत स्पेस से निडर, कॉन्फिडेंट और गर्व से पूर्ण दिखता है।'

***सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर,***

# फलक को छूने की ख्वाहिश-वेव्स ओटीटी

पवन सिंह

फ़लक को छूने की ख़्वाहिश हज़ार दिल में लिए
कि सरगिरां है हमारी उड़ान भी हम भी.."

नबील अहमद "नबील" साहेब का यह शेर है जो दूरदर्शन की नई अंगड़ाईयों पर मौजू है..!! दूरदर्शन अब अपनी परंपरागत छवि को बरकरार रखते हुए एक नई लड़ाई के लिए मैदान में उतर चुका है। दूरदर्शन जिस तरह के विविधतापूर्ण कंटेंट्स को लेकर "वेव्स" के जरिए इंटरटेनमेंट के विशालकाय समर में उतरा है, उसने तमाम ओटीटी प्लेटफार्मों में खलबली मचा दी है। वेव्स ओटीटी ने बेहतरीन कंटेंट् के साथ मनोरंजन के क्षेत्र में एक ऐसी प्रतिस्पर्धा का बिगुल फूंक दिया है कि आने वाले एक साल के भीतर अन्य ओटीटी प्लेटफार्मों को भी यह सोचना पड़ेगा कि केवल गालियां, हिंसा, बलात्कार, सेक्स ही ओटीटी का मूल विषय नहीं हो सकता बल्कि तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें न तो छिपकर देखने की जरूरत है और न कान में लीड लगाकर।

बदलाव की इस आहट से दिल्ली में मंडी हाउस के आसपास फैला सन्नाटा अब टूटने लगा है। एक बार फिर से मंडी हाउस के बाहर निर्माता-निर्देशकों और कलाकारों की आवा-जाही शुरू हो गई है। मंडी हाउस एक बार फिर से 1984 और 1996 के उस वक्त की याद दिलाने लगा है जब यहां पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। धारावाहिक "हम लोग" जो कि 7 जुलाई, 1984 को और "बुनियाद" जो कि 1986 में प्रसारित हुए थे, ने मंडी हाउस को स्टोरी राइटरों, कलाकारों, निर्माता-निर्देशकों...के लिहाज से किसी धार्मिक स्थल के रूप में बदल दिया था। प्रादेशिक स्तर पर एक नया प्लेटफॉर्म खुला और नीम का पेड़, बीबी नातियों वाली.. जैसे धारावाहिकों ने कंटेंट के लिहाज से एक अलग ही लड़ाई शुरू कर दी थी। वह दौर क्या एक बार फिर लौटेगा ? ..और फिर से वही दौर लौटने की आहट ने मंडी हाउस के आसपास के कई थिएटरों- कमानी ऑडिटोरियम, एलटीजी ऑडिटोरियम, श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, त्रिवेणी कला संगम में भी थिरकन पैदा कर दी है..क्योंकि वेव्स ने सैकड़ों कलाकारों को उम्मीदों से भर दिया है। वह ऐसे नये कंटेंट्स की तलाश में लग गया है जिसे परिवार के साथ भी बैठ कर देखा जा सकता है।

दरकते और दहकते हुए सामाजिक ढांचे को फिर से मजबूत करने की दशा व दिशा के साथ वेव्स ओटीटी की एक नई परिभाषा गढ़ना चाहता है। वेव्स भी मोहब्बत की कहानियां ओटीटी पर उतारना चाहता है लेकिन नजाकत और नफासत के साथ। वेव्स ओटीटी की पहचान बन चुके "गालियों और सेक्स" व अश्लीलता से बजबजाये हुए "आइटम सांग" से इतर नये कंटेंट लेकर आ रहा है। कुछ अतीत, कुछ वर्तमान और कुछ भविष्य के कथानकों को समेटकर वेब्स ओटीटी, यह मानक गढ़ना चाहता है कि "चोली के पीछे क्या है"..से इतर कुछ ऐसा गढ़ा-बुना-रचा जाए जो बेटा अपने पिता के साथ और दादा, पोते के साथ देख सके..!!

इसके अलावा वेव्स ओटीटी प्लेटफार्म की सबसे बड़ी ताकत है मुफ्त में मनोरंजन प्रदान करना जिसमें फिल्में, वेब सीरीज, टीवी शो और लाइव टीवी चैनल सब कुछ शामिल हैं..!! भारत में करीब 57 ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं. भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ऑल्ट बालाजी, जियो सिनेमा, जी5, Aha, Hoichoi, सोनी लिव जैसे कई पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म्स के अलग-अलग प्लान्स हैं जबकि वेव्स ओटीटी का कोई प्लान नहीं है, वह मुफ्त है ! ये सारे प्लेटफार्म जहां बोल्ड कंटेंट्स के साथ-साथ, अपराध और भ्रष्टाचार पर जबरदस्त हमलावर हैं और युवाओं के बीच इसीलिए जगह बना चुके हैं. ऐसे में वेव्स ओटीटी इस लड़ाई को कैसे लड़ेगा, यह देखने की बात होगी..!!

मुंबई के एक प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक का कहना है वेव्स के पास खुला आसमान है। वो आसानी से महिलाओं, अधेड़ उम्र व बुजुर्ग दर्शकों को अपने कंटेंट के साथ जोड़ सकता है..उसे मेहनत करनी है युवाओं को जोड़ने की..!! इसके लिए बेहतर होगा कि व्यवस्था पर हास्य-व्यंग्य के जरिए हमलावर हों..!!जैसे फिर से आफिस-आफिस जैसा धारावाहिक नये रूप में लिया गया है। दूरदर्शन ने अपने दौर में तमाम ऐसे कलाकारों, निर्माता-निर्देशकों को मौका दिया जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्रीज में छा गये। कुछ नाम मुझे याद आते हैं. म्युजिक-मस्ती और धूम के जरिए नोमान मलिक ने अन्नू कपूर को मौका दिया. सागर सरहदी ने 1977 में ये इश्क नहीं आसां बनाया और फिर फिल्में

कभी कभी", "सिलसिला", "चांदनी", "बाजार", "दीवाना", "कहो ना... प्यार है" जैसी फिल्मों की पटकथा लिखी और "बाजार" फिल्म का निर्देशन भी किया। फौजी धारावाहिक से शाहरुख खान और कच्ची धूप से भाग्य-श्री का भाग्योदय हुआ। रामानंद सागर, अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, सुनील लाहिरी, बाल कलाकार मयूरेश क्षत्रपति, सुधीर दलवी, और विजयकान्त की पहचान दूरदर्शन से बनी। इसके अलावा मोहन गोखले: "मिस्टर योगी" और "भारत एक खोज" जैसे धारावाहिकों में अभिनय किया।

जसपाल भट्टी: "फ्लॉप शो" जैसे धारावाहिकों के माध्यम से हास्य कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। पंकज कपूर ने "कर्मचक्र" और "ऑफिस ऑफिस" जैसे धारावाहिकों में अभिनय किया। शबाना आज़मी:"कथा सागर" और "अधूरा आदमी" जैसे धारावाहिकों में अभिनय किया।.. कहानीकारों, कलाकारों, निर्माता-निर्देशकों के लिए वेव्स अब एक नई उम्मीद लेकर आया है..!! सूत्रों के अनुसार वेव्स अब मेगा धारावाहिक लेकर आ रहा है जिसमें फिल्मी दुनियां के बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं..जो एक उम्मीद जगाते हैं कि वेव्स ओटीटी, ओटीटी प्लेटफार्मों पर अपनी एक बड़ी पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। फ़हीम जोगापुरी साहेब का एक शेर है-

"वाक़िफ़ कहां ज़माना हमारी उड़ान से
वो और थे जो हार गए आसमान से"

# मनोविकारों से बाहर निकलो : डॉ. नीरज भारद्वाज

डॉ. नीरज भारद्वाज

गुरु पूर्णिमा के दिन संत नगरी ऋषिकेश में पूज्य संतों की शरण में बैठे कर ध्यान लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। संतों के प्रवचनों को सुनने का बहुत ही सुखद अनुभव मिला। विचारणीय है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में साधु, संतों, महात्माओं आदि की बड़ी भूमिका रही है और संत समाज के मार्गदर्शक हैं। संत समाज के मार्गदर्शक होने के साथ-साथ मनुष्य के अंदर की बुराइयों को दूर करते हैं। व्यक्ति के अंदर बैठे अंधकार को मिटाकर उसे शुद्ध-स्वच्छ कर देते हैं। व्यक्ति के मानसिक विकारों को दूर कर पावन पवित्र कर देते हैं। मनुष्य में मनुष्यता का गुण भर देते हैं।

आज भारतीय जनमानस के एक बहुत बड़े वर्ग को मानसिक द्वंद से बाहर निकलना होगा। कितने ही लोग हर दृष्टि से समर्थ होने के बाद भी अपने को असमर्थ कह रहे हैं। विचार किया जाए तो मानव की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर है रोटी, कपड़ा और मकान। जब व्यक्ति को खाने को दो जून रोटी मिल गई है, शरीर ढकने के लिए कपड़ा है और सिर पर छत भी आ गई है। व्यक्ति अपनी जिज्ञासों का फलक क्यों फैला रहा है। सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में राशन दे रही है। फिर भी व्यक्ति क्यों भीख मांग रहा है, वह बार-बार भिक्षुक क्यों बन रहा है ? जिसके चलते विश्व मानचित्र पर भारत की छवि खराब होती है। कितनी ही फिल्मों दिखाया गया है कि विदेशी लोग भारत में घूमने के लिए आते हैं और अपने कैमरे में दर्शनीय स्थलों के फोटो लेने के साथ-साथ भीख मांगते लोगों के भी फोटो खींच लेते हैं। कई पुरानी फिल्मों में तो भीख मांगने को व्यापार के रूप में दिखाया है। किसी भी तीर्थ स्थल पर चले जाओ, भिक्षुक सामान्य जन को घेर लेते हैं। अमर्यादित यह जन समूह अव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। भीख मांगने वालो ने अपने-अपने क्षेत्र बांट रखे हैं।

महानगरीय जीवन में लाल बत्ती पर कितने ही भीख मांगने वाले खड़े रहते हैं। कई बार तो यह लोग गाड़ियों से कीमती सामान भी निकाल लेते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को इस काम में लगाया जाता है जबकि भारत सरकार ने फ्री शिक्षा और मिड डे मील की व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन भी मौन दिखाई देता है।

यह देश मांगने वालों का देश नहीं है, यह देश विश्व का भरण पोषण करने वालों का है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि विश्व भरन पोषण पर जोई। ताकर नाम भारत अस होई।। श्रीभरत जी का चरित्र विश्व के भरण पोषण की बात करता है। भगवान श्रीराम तो स्वयं ही विश्व को चलाने वाले हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमारे संतों ने हमारे शास्त्रों के विषय में बड़ा ही सुंदर बताया, सुनाया और लिखा है। लोगों की बुद्धि से अज्ञान का पर्दा हटाया है, फिर भी लोग अंधकार में क्यों भटक रहे हैं ?

हमारे संत, महात्मा, योगी, विद्वाना आदि बताते-समझाते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का साथ करें जिससे कि आपका विवेक और ज्ञान क्षमता दोनों ही बढ़ जाएं। जब आपका विवेक और ज्ञान क्षमता बढ़ती है तो आपके अंदर के मनोविकार दूर होते हैं। भारतीय समाज में भी हमें इस दृष्टि और दृष्टिकोण को आगे बढ़ना होगा, साथ ही समाज को नई दिशा देनी होगी। मानसिक मनोरोगों से घिरे लोगों को बाहर निकलना होगा। लोगों को राष्ट्र चिंतन करना होगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें बच्चे के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक आदि विकास की बात करते हैं। शारीरिक रूप से तो बच्चा मजबूत हो ही जाता है, उसके शरीर के अंगों में परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता ही है लेकिन क्या वह मानसिक रूप से भी मजबूत बन पाया या नहीं बन पाया है, यह बात सोचने की है। हमारे पुराण, शास्त्र, ग्रंथ आदि हमें मानसिक द्वंद्व से बाहर निकाल कर मनुष्य के अंदर नव चेतना और नव ऊर्जा का संचार भर देते हैं।

हमें अपनी ज्ञान परंपरा को पढ़ना, समझना, जानना होगा। आने वाली पीढियों को उसके बारे में सही से बताना होगा। ज्ञान परंपरा की धारा अविरल है, इसे बहते रहने की जरूरत है, इसे रोकने की जरूरत नहीं है।

***डॉ. नीरज भारद्वाज***

# आकंड़ों में दबती ममता: मातृ मृत्यु दर में देश में अव्वल मध्य प्रदेश

## [गर्भवती महिलाओं की अधूरी यात्रा: मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु की सच्चाई]

मध्य प्रदेश, जहां मातृत्व का पवित्र बंधन जीवन का अनमोल आशीर्वाद है, आज एक दुखद सच्चाई से जूझ रहा है। हर साल लाखों माताएं गर्भावस्था का सफर उम्मीदों और सपनों के साथ शुरू करती हैं, लेकिन कई के लिए यह अधूरा रह जाता है। मां की गोद, जो जीवन का प्रतीक होनी चाहिए, कभी-कभी मौत की ठंडी चादर से ढक जाती है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) २०२२ की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर देश में सर्वाधिक है—प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 159, जो राष्ट्रीय औसत 88 से कहीं अधिक है। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर गंभीर सवाल उठाता है। उच्च शिशु मृत्यु दर के बोझ तले दबा मध्य प्रदेश अब मातृ मृत्यु दर में भी शीर्ष पर है। यह त्रासदी माताओं और उनके परिवारों के साथ-साथ पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं और व्यवस्थाओं को तुरंत सुधारना होगा।

एसआरएस २०२२ की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 159 प्रति लाख जीवित जन्मों पर आई है—14 अंकों की कमी। यह प्रगति सराहनीय है, मगर यह कटु सत्य कि प्रदेश अभी भी देश में सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर के साथ शीर्ष पर है, हमें गहरे चिंतन के लिए विवश करता है। हर साल, करीब २० लाख गर्भवती महिलाओं में से 3100 से अधिक अपने नवजात के जन्म के 4२ दिनों के भीतर जीवन से हाथ धो बैठती हैं। यह आंकड़ा महज संख्या नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की टूटी उम्मीदों और अपूरणीय क्षति की मार्मिक कथा है। ये माताएं केवल अपने बच्चों का भविष्य नहीं, बल्कि समाज की आधारशिला हैं। उनकी मृत्यु सिर्फ व्यक्तिगत शोक नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक ताने-बाने का विघटन है।

मातृ मृत्यु के पीछे प्रमुख कारण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और उनकी निम्न गुणवत्ता है। प्रदेश के लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर (ओटी) अक्सर अपर्याप्त और असुविधाजनक हैं। उदाहरणस्वरूप, लेबर रूम के लिए निर्धारित 15२ अंकों के मूल्यांकन में कई अस्पताल 30 से 95 प्रतिशत के बीच ही स्कोर कर पाते हैं, जो बुनियादी सुविधाओं और मानकों के अभाव को उजागर करता है। इसके अलावा, गायनकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया विशेषज्ञों और शिशु रोग विशेषज्ञों की भारी कमी के चलते सीजेरियन डिलीवरी जैसी आपातकालीन सेवाएं कई अस्पतालों में अनुपलब्ध हैं। प्रदेश में फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू), जहां सीजेरियन सुविधा अनिवार्य है, मात्र 150 के आसपास हैं—यह संख्या इतनी कम है कि अधिकांश गर्भवती महिलाएं समय पर इन तक नहीं पहुंच पातीं।

मातृ मृत्यु के प्रमुख कारणों में एनीमिया, उच्च रक्तचाप और प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच) हैं—ऐसी समस्याएं, जिन्हें समयबद्ध और प्रभावी चिकित्सा हस्तक्षेप से रोका जा सकता है। किंतु मध्य प्रदेश में प्रसव पूर्व जांचों की गुणवत्ता और उपलब्धता गंभीर रूप से अपर्याप्त है। अक्सर गर्भवती महिलाओं की नियमित जांचें लापरवाही का शिकार हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, रक्तचाप की जांच के नाम पर केवल 1२0/80 लिखकर खानापूरी कर दी जाती है, जबकि वास्तव में महिला का रक्तचाप खतरनाक स्तर पर हो सकता है। हीमोग्लोबिन की जांच भी प्राय: उपेक्षित रहती है, जिसके चलते प्रसव के समय एनीमिया की गंभीर स्थिति सामने आती है। जब कोई प्रसूता अस्पताल पहुंचती है, तो उसका हीमोग्लोबिन स्तर तीन-चार ग्राम तक गिर चुका होता है, जिससे उसका जीवन बचाना लगभग असंभव हो जाता है। यह स्थिति न केवल चिकित्सा सुविधाओं की कमी को उजागर करती है, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही और प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) जैसे कार्यक्रमों के बावजूद, मध्य प्रदेश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय असमानताएं चिंताजनक रूप से स्पष्ट हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, और आपातकालीन प्रसूति देखभाल तक पहुंच की अनुपस्थिति मातृ मृत्यु दर को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण प्रसूताओं को अक्सर उचित परिवहन के बिना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय पर चिकित्सा सहायता मिलना दुरूह हो जाता है। इसके उलट, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अपेक्षाकृत बेहतर हैं, पर वहां भी संसाधनों और विशेषज्ञों की कमी बाधा बनी हुई है। मातृ मृत्यु समीक्षा (मैटरनल डेथ रिव्यू) के आधार पर व्यवस्थागत सुधार की दिशा में ठोस कदमों का अभाव इस संकट को और गहराता है, जो तत्काल कार्रवाई की मांग करता है।

मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (२018) के अनुसार, प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 48 थी, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक थी। यद्यपि समय के साथ इसमें कुछ सुधार हुआ है, फिर भी मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जहां शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। समयपूर्व प्रसव, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, और गैर-संस्थागत प्रसव जैसे कारक इस दर को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले गैर-संस्थागत प्रसव संक्रमण और जटिलताओं का जोखिम बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 (२019-२0२1) के अनुसार, प्रदेश में संस्थागत प्रसव की दर 88.6% तक पहुंची है—यह एक सकारात्मक कदम है। किंतु, यह आंकड़ा विकसित देशों की तुलना में कम है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह और भी निचले स्तर पर है, जो तत्काल सुधार की मांग करता है।

मातृ और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) जैसी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की हैं। पीएमएसएमए के अंतर्गत हर महीने की 9, 15 और २1 तारीख को गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच होती है, जिसमें रक्तचाप, मधुमेह और हीमोग्लोबिन जैसे आवश्यक परीक्षण शामिल हैं। वहीं, पीएमएमवीवाई गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। किंतु, मध्य प्रदेश जैसे उच्च जोखिम वाले राज्यों में इन योजनाओं का कार्यान्वयन अभी भी कमजोर है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) को सशक्त करने, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और टेलीमेडिसिन सेवाओं को विस्तार देने, तथा आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को और प्रभावी बनाने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच सके।

मातृ और शिशु मृत्यु के इस संकट से निपटने के लिए केवल नीतियां और संसाधन पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता की सशक्त लहर भी आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व के प्रति जागरूक करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार की जरूरत है। गायनकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, और शिशु रोग विशेषज्ञों की भर्ती व प्रशिक्षण पर तत्काल ध्यान देना होगा। डिजिटल स्वास्थ्य पहल, जैसे यू-विन प्लेटफॉर्म, जो गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण को ट्रैक करता है, को व्यापक स्तर पर लागू करना होगा। साथ ही, मातृ मृत्यु समीक्षा को पारदर्शी और प्रभावी बनाकर प्रत्येक त्रासदी से सबक लेना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी हृदयविदारक घटनाओं को रोका जा सके।

मध्य प्रदेश की यह स्थिति एक गंभीर चुनौती है, पर असाध्य नहीं। केरल, जहां मातृ मृत्यु दर मात्र 30 है, हमारी प्रेरणा है। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में कमी यह संकेत देती है कि सही दिशा में कदम संभव हैं। किंतु इसके लिए सरकार, स्वास्थ्य पेशेवरों और समाज के एकजुट संकल्प की आवश्यकता है। प्रत्येक मां का जीवन अनमोल है, और प्रत्येक शिशु का भविष्य हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश को इस कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए अभी से ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि हर गर्भवती महिला सुरक्षित मातृत्व का सुख अनुभव कर सके और हर शिशु अपनी मां की गोद में मुस्कुराता बड़ा हो।

**प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)**

# डिजिटल स्मृति: क्या हम अपनी यादों को डेटा सेंटर में दफना रहे हैं?



हम इस युग में जी रहे हैं जहाँ हमारी यादों का ठिकाना अब हमारे दिल-दिमाग या पारिवारिक संदूकों में नहीं, बल्कि अनगिनत सर्वरों में कहीं दूर किसी डेटा सेंटर में छुपा बैठा है। कभी तस्वीरें पुराने बक्सों में रखी जाती थीं, जिन्हें बरसों बाद खोलने पर उनकी महक से स्मृतियों की भीनी लहर उठती थी। अब वही तस्वीरें किसी क्लाउड ड्राइव के अनंत फोल्डरों में दबी पड़ी रहती हैं। यह बदलाव जितना सुविधाजनक लगता है, उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि धीरे-धीरे हम अपनी स्मृतियों का भार खुद उठाने की क्षमता खोते जा रहे हैं। डिजिटल स्मृति एक अद्भुत औजार है जिसने हमें अपनी ज़िंदगी के हर छोटे-बड़े पल को स्थायी रूप से सहेजने की शक्ति दी। मोबाइल कैमरे की एक क्लिक में हम किसी दृश्य को फ्रीज कर लेते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इस सुविधाजनक संग्रहण की कीमत क्या है ? हमने अपनी स्मृतियों को अनुभव करने के बजाय संग्रह करने की वस्तु में बदल दिया है। हम किसी त्योहार में अपने प्रियजनों के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर तो ले लेते हैं, लेकिन उस मुस्कान को पूरी तरह जी नहीं पाते। कैमरे के पीछे से देखने की इस आदत ने अनुभवों की आत्मा को छीन लिया है। डिजिटल मेमोरी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह असल में हमारी अपनी स्मृति की दुश्मन बन रही है। जब हम जान जाते हैं कि सबकुछ गूगल फोटोज या आईक्लाउड में सुरक्षित है, तो मस्तिष्क को याद रखने की जरूरत ही कहाँ महसूस होती है ? यह सुविधा धीरे-धीरे हमारी प्राकृतिक स्मरणशक्ति को कुंद कर रही है। आज अगर कोई पूछे कि पिछली गर्मियों की यात्रा में किस दिन क्या किया था, तो हम जेब से मोबाइल निकालकर डेट देखेंगे। क्या यह हमारी मानसिक स्वायत्तता का लोप नहीं है ?

यादों का डिजिटल होना उन्हें निर्जीव भी बना देता है। पहले किसी फोटो एलबम को पलटते हुए उसमें दादी का लिखा कोई छोटा सा नोट, किसी तस्वीर के पीछे पेंसिल से लिखी तारीख, या चाय के दाग का निशान मिल जाता था। उन छूने-सूंघने के अनुभवों में एक आत्मीयता छुपी होती थी। अब सब फाइलें हैं, जिनका कोई रंग-गंध नहीं। वे अपनी टेक्सचर खो चुकी हैं। डेटा सेंटर में कैद ये फोटोज़, वीडियोज़ और चैट हमारे अतीत के निर्जीव दस्तावेज़ बन जाते हैं।

इस डिजिटल संग्रहण की एक और कड़वी सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में भी नहीं। गूगल, ऐप्पल, फेसबुक जैसी कंपनियाँ अनगिनत सर्वरों पर हमारी निजी यादों का व्यापार कर रही हैं। हम हर ऐप को अपनी फोटो गैलरी की अनुमति देकर मानो अपनी यादों की चाबी अनजान हाथों में सौंप देते हैं। उनके ऐल्गोरिद्म हमारी तस्वीरें पढ़ते हैं, चेहरे पहचानते हैं, और हम पर विज्ञापनों की बौछार करते हैं। यह निजता का ह्रास भी है, और एक तरह से हमारी स्मृति का उपनिवेशीकरण भी।

एक सवाल जो आज हमें खुद से पूछना चाहिए, वह यह है कि क्या हमें हर चीज़ को डिजिटल रूप में सहेजने की लत लग चुकी है ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी पल को सिर्फ इसलिए जी रहे हैं ताकि उसे पोस्ट कर सकें ? कई शोध बताते हैं कि लगातार फोटो लेने की आदत से हमारा "प्रेज़ेन्स" यानी उस पल में पूरी तरह मौजूद रहने की क्षमता घटती जाती है। याददाश्त केवल दृश्य संग्रह नहीं होती, उसमें भावनाओं का ताप भी होता है। वह ताप जब छवियों से अलग हो जाए, तो वे महज डिजिटल साक्ष्य बनकर रह जाती हैं।

यादों की डिजिटल क़ैद हमें एक अजीब असुरक्षा में भी डालती है। हार्डड्राइव क्रैश हो जाए, क्लाउड सर्विस बंद हो जाए, अकाउंट हैक हो जाए—तो लगता है मानो हमारी पूरी ज़िंदगी लापता हो गई। पहले स्मृतियाँ हमारे भीतर सुरक्षित होती थीं। अब उनकी रक्षा के लिए हमें पासवर्ड, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अनगिनत बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। यह अनिश्चितता हमें मानसिक रूप से भी अस्थिर बनाती है।

जरूरी यह नहीं कि हम तकनीक से दूर भागें। डिजिटल स्मृति के कई फायदे हैं—पुरानी तस्वीरें एक क्लिक में देखना, कहीं से भी शेयर करना, या परिवार के उन सदस्यों को याद करना जो हमारे साथ नहीं रहे। पर इसकी सीमा तय करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें यह निर्णय लेना होगा कि कौन सी यादें हमारे दिल-दिमाग में रहेंगी और कौन सी क्लाउड में। हमें फिर से यह अभ्यास करना होगा कि कुछ खास पलों को केवल अपनी आत्मा में दर्ज करें, बिना किसी कैमरे के। कभी-कभी किसी दृश्य को बस अपनी आंखों से देख लेना और उसे मन में संजो लेना, एक गहरे तृप्त करने वाला अनुभव होता है। यह स्मृति सच्ची होती है, किसी डिजिटल फाइल से कहीं ज़्यादा जिंदा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यादें केवल "स्टोरेज" की चीज़ नहीं, बल्कि हमारी संवेदनशीलता, हमारी मानवीयता का हिस्सा हैं। डिजिटल स्मृति का यह युग हमें सुविधाएं तो देगा, लेकिन अगर हम सावधान न हुए, तो यह हमारी असली स्मृतियों का कब्रगाह भी बन सकता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम अपनी यादों को सिर्फ डेटा सेंटर में दफन न करें, बल्कि उन्हें अपने मन की सबसे कोमल जगहों में जीवित रखें।

***प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)***

# बदन की नहीं, बुद्धि की बनाओ पहचान बहनों: अश्लीलता की रील संस्कृति पर एक सवाल

प्रियंका सौरभ

हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ स्क्रीन पर दिखना असल में जीने से ज़्यादा जरूरी हो गया है। जहां ज़िंदगी कैमरे के फ्रेम में सिमट गई है, और इंसान का मूल्य उसके 'लाइक', 'फॉलोवर' और 'व्यूज़' से तय होता है। इसी डिजिटल होड़ में स्त्रियों की अभिव्यक्ति भी एक अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई है — जहां रील बनाना कोई बुरा काम नहीं, लेकिन रील के बहाने स्त्री की गरिमा और उसकी सामाजिक छवि का बेशर्म चीरहरण किया जा रहा है।

जिम, मॉल, सड़क, बाथरूम और बेडरूम— हर कोना अब कंटेंट स्टूडियो बन चुका है। कुछ लड़कियाँ सोशल मीडिया पर जिस तरह की अश्लील और भद्दी रील्स बना रही हैं, वह केवल खुद की नहीं, समूची नारी जाति की गरिमा पर धब्बा बन रही है। क्या आपको सच में लगता है कि महज ₹वायरल₹ हो जाने से कोई ताक़तवर बनता है?

एक औरत के पास उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मसम्मान और विवेक होता है। आज जो लड़कियाँ एक्सरसाइज के नाम पर ऐसे कपड़े पहन रही हैं कि देखना भी शर्मिंदगी पैदा करे, वे शायद यह नहीं जानतीं कि वे नारी मुक्ति नहीं बल्कि नारी बाजारीकरण का प्रचार कर रही हैं। शरीर दिखाकर पहचान बनाना कोई गर्व की बात नहीं। अगर रील्स ही बनानी हैं, तो क्यों न ऐसी रील बनाओ जिसमें आपकी कला, मेहनत, सोच और संवेदना झलके?

आज हर तीसरी रील में ₹पिछवाड़ा₹ फ्रेम के बीच में है, कैमरा कमर पर ज़ूम करता है, और कैप्शन होता है —"₹क्लासी एंड सेक्सी!₹ क्या यही स्त्री की परिभाषा बनती जा रही है?

स्त्री आंदोलन कभी इस उद्देश्य से नहीं चला था। हमने शिक्षा, समानता, आज़ादी और आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ी थी, न कि मंच पर खड़े होकर अंग प्रदर्शन की। जो लोग कहते हैं, ₹ये स्त्रियों की आज़ादी है", उनसे पूछिए—क्या शरीर को उत्पाद बनाना आज़ादी है या आधुनिक गुलामी?

और यह दोष सिर्फ उन लड़कियों का नहीं है जो ऐसी रील्स बनाती हैं। यह समाज का भी अपराध है—खासतौर पर पुरुषों का। यही पुरुष ऐसी वीडियो पर मिलियन-मिलियन व्यूज देते हैं, लाइक ठोकते हैं, फिर कमेंट में नैतिकता का भाषण भी पेलते हैं। एक ही वीडियो में पुरुष की आँखें भी डोलती हैं और उंगलियाँ भी नैतिकता टाइप करती हैं। यह दोगलापन बंद होना चाहिए।

सोचिए, क्या होगा जब कोई छोटी बच्ची यह सब देखकर बढ़ेगी? जब वह देखेगी कि ज़्यादा अंग दिखाने वाली को ज़्यादा लाइक मिलते हैं, तो वह किस दिशा में जाएगी? यह रील संस्कृति, स्त्रीत्व को छीनने की चुपचाप होती साजिश है। डिजिटल ग्लैमर की इस दौड़ में हम स्त्री को फिर से उस स्थान पर ले जा रहे हैं जहाँ उसे सिर्फ 'देखे जाने' की वस्तु बना दिया गया था।

आज़ादी की सही परिभाषा वो होती है जिसमें स्त्री खुद के लिए जीती है, न कि समाज के क्लिकबाज़ी वाले बाजार के लिए। एक लड़की सुंदर हो सकती है, फैशनेबल भी, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वह हर बार अपनी देह को ही सेल करे? क्या सोच, क्या विचार, क्या चरित्र, क्या संघर्ष—ये सब सिर्फ उपन्यासों की बातें रह गई हैं?

दूसरी तरफ, जिन प्लेटफॉर्म्स को समाजिक सुधार का औजार माना गया था—जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक—उन्हें हमने डिजिटल कोठा बना डाला है। यह केवल सरकार की असफलता नहीं है, बल्कि हम सब की चुप्पी का परिणाम है।

यह लड़ाई सिर्फ महिलाओं की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की होनी चाहिए जो एक स्वस्थ, गरिमामय, और नैतिक समाज की कल्पना करता है। जो चाहता है कि उसकी बेटी, बहन, दोस्त या पत्नी डिजिटल दुनिया में अपने टैलेंट से पहचानी जाए, न कि अपनी कमर के घुमाव से।

अब समय आ गया है कि स्त्रियाँ खुद आगे बढ़कर कहें—"बस बहुत हुआ।"

रील्स बनानी हैं, बनाओ, लेकिन सोच से बनाओ।

डांस करो, पर आत्मा से—not कैमरे की भूख से।

हंसाओ, सुनाओ, सिखाओ, जोड़ो—क्योंकि स्त्री सिर्फ आकर्षण नहीं, प्रेरणा होती है।

और पुरुषों से भी यही कहना है—अब अपने क्लिक से समाज को मत चलाओ।

अगर अश्लीलता बंद करनी है, तो उसे देखना बंद करो।

रील्स वायरल तब होती हैं जब उन्हें देखे जाने वाले आंख मूंद लेते हैं और दिल खोल देते हैं।

एक बात और—जो लड़कियाँ यह सोचती हैं कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वे ये समझें कि पसंद और उपभोग में फर्क होता है।

एक को देख कर सम्मान मिलता है, दूसरे को देख कर हवस जागती है।

आप खुद तय करें, आप कौन सी नज़रों में आना चाहती हैं?

शायद अब वक्त है एक नई डिजिटल क्रांति का,

जहाँ स्त्री के हाथ में मोबाइल हो—पर कैमरे के सामने न शरीर, बल्कि विचार हों।

---

"रील में न खोओ बहना, सोच को आवाज़ दो,
जो तुम हो भीतर से, वही असली साज़ दो।
बदन की नहीं, बुद्धि की बनाओ पहचान,
यही है स्त्री की सबसे ऊँची उड़ान!"

## "कुत्ते को राजा, इंसान को भिखारी!"

- प्रियंका सौरभ

कुत्ते को गाड़ी में बैठा दिया,
बापू को धूप में छोड़ दिया।
पंखा चला कुत्ते की खातिर,
माँ को पसीने में तोड़ दिया।

कुर्सी पर बैठा पालतू राजा,
घर में इंसान बने मज़दूर।
बिल्ली के दूध में बादाम,
बच्चे को रोटी अधपकी भरपूर।

वो इंसान जो बोल न पाए,
प्यारा लगे, दिल छू जाए।
जो अधिकार मांगे, सच बोले,
वो बुरा लगे, दूरी बनाए।

तोते से कहते हैं "जानू",
बेटे को सुनाते हैं ताने।
पक्षियों को देते हैं प्रेमपत्र,
बीवी की चिट्ठी फाड़ बहाने।

₹स्नानगृह₹ बना है कुत्ते का,
दवा नहीं है दादी के पास।
बर्थडे केक है बिल्लियों का,
भूखा बच्चा देखे उदास।

करुणा अब कपड़ों की है,
जो बोल न सके, उसी पर हो।
जो जवाब दे दे, स्वाभिमानी,
वो घर से बाहर, उसके लिए रो?

हर गली में डॉग शो चलता,
हर मोहल्ले में पंछी महोत्सव।
इंसानों का मेला उजड़ रहा,
ये नया 'सभ्यता-उत्सव'।

करुणा हो सब जीवों के लिए,
यह हम भी मानें बारम्बार।
पर इंसान से नफरत कर के,
पशु-प्रेम का क्या सत्कार?

माँ की दवा, बाप का चश्मा,
बच्चे की कापी, भूखे की थाली —
इनसे बड़ा हो जाए अगर
कुत्ते का स्वेटर, तो हाय! बेहाली!

अब पोस्टर लगे हैं दीवारों पर —
"कुत्ते को मत सताना जी!"
और चौराहे पर आदमी भूखा,
"रोटी दो!" — चुप है दुनिया जी।

रिश्ते टूटे, संवाद बिछुड़े,
आँगन में अब चुप्पी है।
कुत्ते की दुम में घंटी बँधे,
घर-घर में यह नई विपत्ति है।

## कोख में सिसकती बेटी

(कहानी) लेखिका: प्रियंका सौरभ

कोख में किसी बच्चे की पहली चीख, बाहर आने के बाद की नहीं होती। वह तो भीतर ही कहीं, सिसकती, सहमी, डरी हुई गूंजती रहती है... जब वह समझ जाती है कि उसे इस दुनिया में आने की इजाज़त शायद न मिले।

सोनोग्राफी मशीन की स्क्रीन पर नन्हा सा आकार हिल रहा था — धड़कता हुआ, जीता-जागता, इंसान बनने की जद्दोजहद करता हुआ। डॉक्टर ने अपनी निगाहें स्क्रीन से हटाकर धीरे से कहा, "बेटी है।"

उसके बाद जैसे सन्नाटा छा गया।

आरती की साँसें जैसे रुक गईं। सामने बैठा उसका पति विक्रम, जो अब तक मुस्करा रहा था, अब कुर्सी की पुश्त पर झुक गया।

डॉक्टर ने आगे कुछ नहीं कहा। वह जानती थी, कहने की ज़रूरत नहीं थी।

---

आरती 26 साल की थी, गाँव से शहर ब्याह कर आई थी। हँसमुख, पढ़ी-लिखी, सपनों में रंग भरने वाली। शादी के दो साल बीते थे, ससुराल वालों का एक ही राग था — ₹पोता चाहिए, खानदान का दीपक चाहिए।"

जब आरती ने पहली बार गर्भधारण किया, तो सास ने पहले ही कह दिया था, "बेटी निकली तो जिम्मेदार तुम होगी।"

पहली बार डर उसकी कोख में पैबस्त हुआ।

लेकिन वह बेटा निकला — अर्जुन।

खुशियाँ मनाई गईं, मिठाइयाँ बांटी गईं। आरती को भी माँ बनने का सुख मिला। पर जो माँ थी, वही अब 'मशीन' मानी जाने लगी।

---

"दूसरा बेटा हो, तो घर की ताकत बढ़े,"

"बेटी हो गई तो क्या होगा?"

"बेटी बोझ होती है।"

ऐसे ही वाक्य थे जो हर दिन उसकी नसों में उतरते जा रहे थे।

इस बार भी आरती गर्भवती थी, और रिपोर्ट ने बता दिया था — बेटी है।

विक्रम ने घर आते ही गुस्से में कहा, "अबॉर्शन करवा दो।"

आरती रो पड़ी, "वो भी तो बच्ची है... हमारी बच्ची।"

विक्रम चीखा, "मुझे बहस नहीं चाहिए, फैसला चाहिए!"

---

रात भर वह चुप रही। वह जानती थी कि अगली सुबह उसे एक "गलत गर्भ" को हटाने के लिए ले जाया जाएगा।

लेकिन उस रात, पहली बार उसने अपनी कोख से बात की।

"बेटी," उसने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, "माफ करना... मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं तुझे वो दुनिया नहीं दे पाऊंगी जो तुझे चाहिए।"

और तभी,

एक बहुत धीमी, अनकही आवाज़ आरती के भीतर गूंज उठी —

"माँ, मैं आना चाहती हूँ। मैं इस अंधेरे कोनों को छोड़कर तेरी गोद में छुपना चाहती हूँ।

मैं सांस लेना चाहती हूँ, तितलियों से बातें करना चाहती हूँ, पिता की अंगुली पकड़कर चलना चाहती हूँ।

क्या तुम मेरी पहली रक्षक नहीं बन सकती माँ?"

आरती सिहर गई।

क्या वाकई कोख में भी कोई आवाज़ होती है?

या शायद, यह उसकी अंतरात्मा थी जो अब तक चुप थी।

--

अगली सुबह सब तय था।

क्लीनिक का नाम था —"जीवन समाधान सेंटर"

कितनी विडंबना थी — जहां जीवन को 'समाप्त' किया जाता है, वहाँ का नाम 'जीवन समाधान' था।

आरती को स्ट्रेचर पर लिटाया गया।

डॉक्टर ने औपचारिकता पूरी की।

आरती की आँखों से आँसू बहते जा रहे थे।

और तभी...

"रुकिए!"

आरती चिल्ला पड़ी —

"मैं ये गर्भपात नहीं करवाऊंगी!"

सन्नाटा।

डॉक्टर चौंक गए, विक्रम आगबबूला हो गया।

"तू पागल हो गई है क्या?"

"हाँ, अगर बेटी को बचाना पागलपन है, तो हाँ... मैं पागल हूँ!"

आरती उस दिन पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई थी।

उसकी आवाज़ में न कोमलता थी, न डर — बस साहस था।

---

वह घर नहीं लौटी।

अपनी बहन के घर जाकर रहने लगी।

विक्रम ने बात करना बंद कर दिया।

सास ने मोहल्ले में बदनामी करवा दी।

"बहू बगावत कर गई," वो कहती।

लेकिन आरती ने हार नहीं मानी।

वह अपनी बच्ची के लिए जी रही थी।

हर रोज़ जब वो पेट पर हाथ रखती, तो महसूस करती — एक नन्हा जीवन भीतर उग रहा है, जिसे जड़ से काटने की इजाज़त वह नहीं दे सकती।

---

समय बीता।

नौ महीने पूरे हुए।

और एक दिन आरती माँ बनी — बेटी की माँ!

बेटी का नाम रखा — नयना

क्योंकि अब वह आँखे खोलकर दुनिया को नया रूप दिखाना चाहती थी।

नयना की आँखें बड़ी और चमकदार थीं, जैसे उसके भीतर जीवन की लपटें जल रही हों।

---

आरती ने एक एनजीओ जॉइन किया — 'कोख की पुकार'।

वह अब उन महिलाओं से मिलती, जो कोख में बेटियों को खो चुकी थीं या खोने वाली थीं।

वह बोलती, लिखती, लड़ती — कभी कानून के दरवाज़े पर, कभी पंचायत के चौपाल में।

आरती ने न केवल बेटी को जन्म दिया, बल्कि अपने भीतर की औरत को भी पुनर्जन्म दिया।

एक दिन वह गाँव में एक बैठक में गई जहाँ लड़कियों की भ्रूणहत्या पर चर्चा हो रही थी।

वहाँ उसने विक्रम को देखा।

अब उसकी आँखों में पछतावे की परछाई थी।

बोलते हुए आरती की आवाज़ थरथराई, पर रुकी नहीं —

"माँ होना साहस है।

बेटी को जन्म देना एक जिम्मेदारी है,

लेकिन बेटी को बचाना — एक क्रांति है।

और आज मैं कह सकती हूँ — मैंने क्रांति की है।"

हॉल तालियों से गूंज उठा।

---

कई वर्षों बाद...

आरती अब एक जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता थी।

नयना बड़ी हो गई थी — 12वीं की बोर्ड परीक्षा में राज्य की टॉपर।

पत्रकारों ने पूछा, ₹आपको क्या बनना है?₹

नयना मुस्कराई और बोली —

₹मैं बेटी बनकर माँ का सपना पूरा करूंगी — मैं डॉक्टर बनूंगी, ताकि कोई कोख में सिसकती बेटी फिर न मारी जाए।₹

---

आज भी कई जगह बेटियाँ कोख में दम तोड़ रही हैं।

उनकी सिसकियाँ ना तो सुनाई देती हैं, ना दिखाई,

लेकिन कहीं कोई आरती, फिर खड़ी हो जाती है —

अपनी बेटी के लिए,

हर बेटी के लिए।

क्योंकि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती,

वह समाज के अंधकार में दीप भी जलाती है।

## एक अगस्त से सात दिन झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

**रांची** -झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा तथा 7 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान दो दिनों का अवकाश है. इस मानसून सत्र में सिर्फ पांच कार्यदिवस होंगे. मंगलवार को षष्ठम् झारखंड विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी किया गया है. इसके अनुसार चार अगस्त को सदन में प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा. पांच अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट पारित हो जाएगा.

झारखंड विधानसभा में एक अगस्त को शपथ ग्रहण (यदि हो तो), शोक प्रकाश (यदि हो तो) और विधानसभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी. दो अगस्त और तीन अगस्त को मानसून सत्र नहीं चलेगा. दोनों दिन अवकाश रहेगा.

चार अगस्त को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल होगा. सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. पांच अगस्त को प्रश्नकाल रहेगा. वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद-विवाद और मतदान के बाद इसे पारित किया जाएगा. छह अगस्त को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो तो) होंगे. आखिरी दिन सात अगस्त को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो तो) एवं गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) होंगे. इसके साथ ही मानसून का यह छोटा सत्र संपन्न हो जाएगा।

## राहुल गांधी ने मृतक सौम्याश्री के परिवार से फ़ोन पर बात की; घटना की जानकारी ली

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

**भुबनीश्वर** : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बालासोर फ़कीरमोहन कॉलेज की छात्रा सौम्याश्री की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बुधवार यानी आज मृतक सौम्याश्री के पिता से फ़ोन पर बात की। उन्होंने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के ज़रिए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उन्हें इस दुख की घड़ी में मज़बूत बने रहने की सलाह दी। इसके अलावा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मृतक सौम्याश्री के पिता से घटना की जानकारी ली। सौम्याश्री को न्याय मिलने तक कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगी। राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना में शामिल आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुँचाया जाएगा।

14 दिनों के संघर्ष के बाद, सौम्याश्री त्रियाकम सोमवार रात ज़िंदगी की जंग हार गईं। एम्स, भुवनेश्वर में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल, मंगलवार को उनके पैतृक गांव पलासिया में किया गया। उनके भाई मुखाग्नि ने सुझाव दिया है कि उन्हें कर्ज चुका देना चाहिए। सौम्याश्री तारिका फकीरमोहन कॉलेज में इंटीग्रेटेड बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। उसने उक्त विभाग के एचओडी समीर कुमार साहू पर शोषण का शिकार होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कॉलेज अध्यक्ष से शिकायत की HOD ने मुझे बार बार फेबर मांग रह है । एचओडी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय,प्रिंसिपल ने इसे दबाकर घटना को सुलझाने की कोशिश की। सौम्याश्री इसे आसानी से पचा नहीं पाई। अपने संघर्ष को जारी रखते हुए, उन्होंने एक्स के माध्यम से बालासोर एसपी, सांसद और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। हालांकि, कहीं से भी न्याय नहीं मिलने से निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। उसने कॉलेज परिसर में पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली।

## विपक्ष की घेराबंदी: बीजद में हड़कंप, युवा कांग्रेस में हड़कंप..

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

**भुबनेश्वर:** चारों तरफ से घिर गए.. भुवनेश्वर में घिर गए, बालासोर में भी घिर गए। विपक्ष ने राजधानी की छाती पर सरकार को घेरा। बीजद दहाड़ा, कांग्रेस धराशायी हुई और वामपंथी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक तरफ बीजद अपनी ताकत से राज्य सरकार को घेरने की योजना बना रही थी और शहर में आई ही थी कि पुलिस ने लोक सेवा भवन जाते हुए बीजद कार्यकर्ताओं को रोक लिया। बस में तब विरोध और विरोध का भयावह दृश्य देखने को मिला। बीजद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज छात्र की मौत के मामले में न्याय की मांग की और मोहन सरकार की गिरफ्तारी का विरोध किया और पुलिस के साथ उनकी पहली मुठभेड़ हुई। जब पुलिस ने सैकड़ों बीजद कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें करके उन्हें रोकने की कोशिश की, तो स्थिति खतरनाक हो गई और उन्होंने आंसू गैस और रबर की गोलियों का सहारा लिया। जिसमें कई बीजद नेता घायल हो गए। बॉबी दास, डैनी घाडेई, सुलता देव, प्रमिला

मल्लिक, सुनील मोहंती, विश्व मल्लिक, जीतू बलवंतराव, संजीव मल्लिक जैसे नेता घायल हो गए और उन्हें विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में भर्ती कराया गया, जबकि बॉबी दास को अपोलो के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

एक ओर, बीजद लोअर पीएमजी में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, वहीं दूसरी ओर, युवा कांग्रेस ने बिना किसी तैयारी के अचानक मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर लिया। हालाँकि पुलिस को बीजद के विरोध प्रदर्शन की सूचना पहले ही दे दी गई थी, लेकिन युवा कांग्रेस का अचानक पहुँचना पुलिस के बस की बात नहीं थी। इस बीच, एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताया कि युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और मोहन सरकार को जगाने के लिए गीत गाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। दूसरी ओर, वामपंथी दलों ने भी अचानक लोअर पीएमजी में आकर नारेबाजी की है।

इस बीच, राजा स्वैन के नेतृत्व में बीजद सदस्य लोक सेवा भवन में घुस गए और कहा कि विधानसभा के बाहर और अंदर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दोनों पार्टियों के विरोध प्रदर्शन के कारण सड़कें जाम होने के कारण कई रास्ते सील कर दिए गए हैं। राजभवन चौक से एजी चौक तक, एजी चौक से विधानसभा तक, लोक सेवा भवन के पीछे वाली सड़क भी सील है और आम लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है।

लोग राजनीति को लेकर आक्रोशित दिख रहे हैं और एबीवीपी ने निर्भया जैसा हल्का कानून लाने की मांग की है। छात्र कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एबीवीपी द्वारा बनविहार चौक पर हाईवे जाम कर दिया है।

## 700 साल पुरानी प्रसिद्ध 16 भुजी दुर्गा की देउली मंदिर बना रणक्षेत्र

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

**रांची।** कभी उत्तर कलिंग, कालान्तर मे मुगल , अंग्रेज फिर बिहार होते हुए अब झारखंड स्थित भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आराध्या सोलह भुजी मां दुर्गा की 700वर्ष पुरानी दिऊड़ी (देउल- का शाब्दिक अर्थ उत्तर भारत का संस्कृत के बाद एकमात्र शास्त्रीय भाषा ओड़िया भाषा में मंदिर होता , जगन्नाथ मंदिर पुरी भी बडो देऊल कहलाता ) मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर आज एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया. करीब 8 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाना हैं. मंगलवार को यहां जब संवेदक ने दोबारा निर्माण कार्य शुरू कराया. तो इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर पहुंच गये और विरोध जताने लगे. स्थानीय लोग उग्र हो गये. इनमें अधिकतर स्थानीय महिलाएं थीं. देखते ही देखते मंदिर परिसर रणक्षेत्र बन गया. रैपिड एक्शन फोर्स के महिला व पुरुष के जवानों से महिलाएं उलझ पड़ीं. हो-हंगामा के बीच परिसर में ही विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गयी.

स्थिति के तनावपूर्ण होते ही बुंडू एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा, एसडीपीओ ओम प्रकाश समेत तमाड़ थाना प्रभारी रोशन कुमार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. सावधानी के तौर पर प्रशासन ने नेता पूर्णचंद सिंह मुंडा को एहतियातन हिरासत में लिया. अपने नेता को पुलिस हिरासत में देख बुलडोजर चलाने का विरोध कर रहे महिला-पुरुष और अधिक उग्र हो गये. अंततः पूर्णचंद्र सिंह मुंडा को पुलिस ने हिरासत से मुक्त किया.

प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद माहौल शांत हुआ और सौंदर्यीकरण कार्य दोबारा शुरू कराया गया. एहतियात के तौर पर मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गयी है और प्रशासन की निगरानी में काम जारी है. प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को उनके फायदे बताते हुए कार्य प्रारंभ करने पर जोर दिया. बताया गया कि मंदिर परिसर में पक्की दुकानें, मैरिज हॉल, धर्मशाला आदि कई जन उपयोगी योजनाएं शामिल हैं. जिससे मंदिर में पूजा अर्चना करने आनेवाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी.

ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर परिसर के आसपास वर्षों से उनकी दुकानें लग रही है. सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान ये दुकानें टूट जायेंगी और काम पूरा होने के बाद उन्हें दोबारा दुकानें मिलेंगी या नहीं. इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. इसी वजह से वे लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं.

यह मंदिर टाटा से रांची हाईवे एन एच 33 पर एक ऐतिहासिक मंदिर है 16 भुजावाली दुर्गा की मूर्ति है जो खूंटी के तमाड़ इलाके में सड़क किनारे लोगों के भक्ति व श्रद्धा का प्रतिक है ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023